RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 332
दि. 05.04.2026,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

भाजपा का चुनावी महासंग्राम: मोदी, शाह और शीर्ष नेताओं के नेतृत्व में प्रचार की नई रणनीति

नई दिल्ली। पांच राज्य विधानसभाओं के चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने चुनावी अभियान को पूरी ताकत के साथ तेज कर दिया है। पार्टी का उद्देश्य न केवल सत्ता बनाए रखना है, बल्कि दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर में अपनी पकड़ को और मजबूत करना भी है। इस बार भाजपा ने केंद्रीय नेतृत्व, राज्य के मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं को रणनीतिक रूप से हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में उतार कर चुनावी तैयारियों को चरम पर पहुँचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अभियान के केंद्र में हैं। प्रधानमंत्री ने असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पद्दुचेरि का दौरा किया और जनसभाओं, रोड शो और सम्मेलनों के माध्यम से पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया। प्रधानमंत्री के चुनावी दौरे की खासियत यह है कि उन्होंने हर राज्य की स्थानीय और राष्ट्रीय जरूरतों को समझते हुए कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण जनता को जोड़ने पर भी विशेष ध्यान दिया। मोदी की उपस्थिति से न केवल पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह बना है, बल्कि मतदाताओं में भी भाजपा के पक्ष में विश्वास का माहौल तैयार हो रहा है।

भाजपा के अन्य शीर्ष नेता भी लगातार चुनावी मैदान में सक्रिय हैं। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और पूर्व अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने लगभग हर राज्य में दौरे किए और विभिन्न जनसभाओं में लोगों से सीधे संवाद किया। उनके कार्यक्रमों की विस्तृत योजना बनाई गई है ताकि हर क्षेत्र में प्रभावी प्रचार सुनिश्चित किया जा सके। शाह की रणनीतिक सूझ-बूझ, राजनाथ सिंह का अनुभव और नितिन नवीन की संगठनात्मक क्षमता मिलकर भाजपा के प्रचार अभियान को सशक्त बना रही है।

सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व ही नहीं, बल्कि राज्य के मुख्यमंत्रियों को भी अभियान में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी

आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, राजस्थान के भजनलाल शर्मा, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय और दिल्ली की रेखा गुप्ता ने अपने-अपने राज्यों में सक्रिय प्रचार किया। मुख्यमंत्री अपने अनुभव और स्थानीय स्तर की समझ का उपयोग करते हुए मतदाताओं तक भाजपा की नीतियों और योजनाओं की जानकारी पहुँचा रहे हैं। इससे पार्टी के संदेश का असर आम जनता तक सीधा पहुँच रहा है और संगठन को मजबूती मिल रही है।

सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के लगभग 30 चुनावी कार्यक्रम तय किए गए हैं, जिनमें रोड शो, जनसभाएं और सम्मेलन शामिल हैं। वहीं अमित शाह, नितिन नवीन, राजनाथ सिंह और जे.पी. नड्डा के 50 से अधिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई है। भाजपा ने हर कार्यक्रम को क्षेत्रीय समीकरणों, उम्मीदवार की लोकप्रियता और स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखकर रणनीतिक रूप से आयोजित किया है। यह व्यापक योजना पार्टी के प्रचार अभियान की मजबूती और प्रभावशीलता को दर्शाती है।

पार्टी ने रणनीतिक सीटों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है। केंद्रीय मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं को ऐसे क्षेत्रों में तैनात किया गया है, जहाँ मतदाताओं को जोड़ने और पार्टी के संदेश को फैलाने की आवश्यकता अधिक है। उम्मीदवारों की जरूरतों और स्थानीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों को इस प्रकार से आयोजित किया जा रहा है कि अधिकतम प्रभाव सुनिश्चित हो। इस रणनीति का उद्देश्य न केवल चुनाव जीतना है, बल्कि दीर्घकालिक रूप से पार्टी की संगठनात्मक शक्ति को बढ़ाना भी है। पूर्वोत्तर में असम और पश्चिम बंगाल भाजपा के लिए सबसे अहम राज्य हैं। असम में पार्टी सत्ता में है और उसे बनाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई है। यहाँ मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और अन्य नेताओं की सक्रियता ने चुनावी तैयारियों को मजबूती दी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा मुख्य विपक्षी दल होने के साथ ही सत्ता परिवर्तन की दावेदार भी है। इस राज्य में पार्टी ने मोदी और शाह के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर जनसभाओं और रोड शो का आयोजन किया है। पश्चिम बंगाल में पार्टी ने स्थानीय मुद्दों और विकास योजनाओं को जनता तक पहुँचाने पर विशेष ध्यान दिया है। दक्षिण भारत में भाजपा की पकड़ मजबूत करना भी अभियान का मुख्य लक्ष्य है। तमिलनाडु, केरल और पद्दुचेरि में पार्टी ने अपने शीर्ष नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के साथ गठबंधन के बावजूद भाजपा पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है और सहयोगी दल को रणनीति में खुली छूट दी गई है। यहाँ भाजपा का उद्देश्य मत प्रतिशत बढ़ाना और स्थानीय निकायों में अपनी भूमिका मजबूत करना है।

केरल में भाजपा के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण है। यह राज्य राजनीतिक और वैचारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन पार्टी को अब तक बड़ी सफलता नहीं मिली है। इस बार भाजपा ने सामाजिक समीकरणों और स्थानीय मुद्दों को साधते हुए अपने प्रचार अभियान को और प्रभावी बनाया है। पार्टी का लक्ष्य वोट प्रतिशत बढ़ाना और कुछ महत्वपूर्ण सीटें जीतना है, ताकि भविष्य में राज्य में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की जा सके।

पद्दुचेरि में भाजपा जूनियर पार्टनर के रूप में गठबंधन सरकार बनाए रखने के प्रयास में लगी हुई है। पार्टी ने यहाँ भी वरिष्ठ नेताओं को चुनावी प्रचार के लिए तैनात किया है। इस राज्य में गठबंधन के समीकरण और स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनाई गई है। भाजपा का यह व्यापक चुनावी अभियान केवल प्रचार तक सीमित नहीं है। यह संगठनात्मक शक्ति को मजबूत करने, मतदाताओं से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करने और पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुँचाने का माध्यम भी है। पार्टी ने प्रत्येक राज्य, जिले और विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग रणनीति बनाई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी क्षेत्र में प्रचार अभियान कमजोर न पड़े और सभी मतदाता भाजपा की उपलब्धियों और योजनाओं से परिचित हों।

इस तरह भाजपा का यह चुनावी महासंग्राम मोदी, शाह और वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में पूरे देश में चल रहा है। असम और बंगाल में सत्ता बनाए रखने और दक्षिण भारत में पकड़ मजबूत करने की रणनीति के तहत पार्टी ने हर संसाधन का इस्तेमाल किया है। रोड शो, जनसभाएं, सम्मेलन और व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से पार्टी जनता तक सीधे संदेश पहुँचा रही है। इसके साथ ही राज्य और केंद्र के नेताओं की सक्रियता पार्टी के प्रचार अभियान को और प्रभावी बना रही है।

हर झूठ का पर्दाफाश करूंगा: राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को किया खारिज

नई दिल्ली। राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने हाल ही में आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने इसे सुनियोजित अभियान करार देते हुए कहा कि उनके खिलाफ लगातार झूठे आरोप फैलाए जा रहे हैं। चड्ढा ने 'एक्स' पर अपने वीडियो संदेश के माध्यम से स्पष्ट किया कि एक ही झूठ को बार-बार दोहराया जा रहा है, लेकिन वह हर झूठ का पर्दाफाश करेंगे। उन्होंने कहा, "मैं घायल हूं, इसलिए घातक हूं," यह कहते हुए उन्होंने अपनी सक्रियता और संघर्षशीलता का अहसास कराया।

चड्ढा ने बताया कि आप नेताओं ने उन पर तीन प्रमुख आरोप लगाए हैं। उन्होंने इन तीनों आरोपों का पूरी तरह से खंडन किया और कहा कि इनका जवाब देना बेहद जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संसद में उनका ध्यान जनता के मुद्दों को उठाने और सरकार पर दबाव बनाने तक सीमित है। हंगामा करने, माइक तोड़ने या कुर्सियां फेंकने का कभी उनका उद्देश्य नहीं रहा। उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि वे संसद में ऐसा एक भी उदाहरण पेश करें, जहां उन्होंने वॉकआउट में विपक्ष का साथ न दिया हो। चड्ढा ने यह भी कहा कि इस बात की पुष्टि राज्यसभा परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से आसानी से की जा सकती है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त से संबंधित प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने का आरोप भी चड्ढा ने पूरी तरह खारिज किया। उन्होंने बताया कि किसी भी पार्टी नेता ने औपचारिक या अनौपचारिक रूप से उनसे इस पर हस्ताक्षर करने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के कई अन्य सांसदों ने भी इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। चड्ढा ने स्पष्ट किया कि उनके लिए संसद में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं, जैसे कि जीएसटी, आयकर, दिल्ली में वायु प्रदूषण, पंजाब में जल संबंधी समस्याएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रेल यात्री से जुड़े मुद्दे, बेरोजगारी और महंगाई।

राज्यसभा सदस्य के रूप में राघव चड्ढा का कहना है कि उनका प्राथमिक उद्देश्य केवल जनहित के मुद्दों को संसद में उठाना और सरकारी नीतियों पर जवाबदेही सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि उनकी सक्रियता का केंद्र हमेशा जनता और उनके अधिकार रहे हैं, न कि किसी पार्टी विरोधी अभियान या व्यक्तिगत विवाद। उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं की आलोचना को केवल राजनीतिक प्रक्षेपण करार दिया और कहा कि वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है।

चड्ढा ने यह भी बताया कि विपक्ष के रूप में उनके काम करने का तरीका पारदर्शी और अनुशासित रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी ऐसे कदम नहीं उठाए जो संसद की गरिमा या नियमों का उल्लंघन करते हों। उनका कहना है कि विपक्ष का कर्तव्य केवल हंगामा करना नहीं, बल्कि ठोस और व्यावहारिक बहसों के माध्यम से जनता के हित में नीतियों पर सवाल उठाना है।

उनका यह बयान उस समय आया है जब राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई है कि आम आदमी पार्टी उनके खिलाफ प्रचार अभियान के तहत व्यक्तिगत आरोपों और अफवाहों का सहारा ले रही है। राघव चड्ढा ने इसे न केवल असत्य बताया बल्कि इस अवसर का उपयोग करते हुए कहा कि वह इन झूठों का पर्दाफाश करने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। उन्होंने मतदाताओं और जनता से अपील की कि वे किसी भी अफवाह या अनसत्य प्रचार से प्रभावित न हों और तथ्यपरक जानकारी पर भरोसा करें।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, राघव चड्ढा का यह कदम न केवल अपनी छवि को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे आम आदमी पार्टी के अभियान की वैधता पर भी सवाल उठते हैं। उन्होंने अपने वीडियो संदेश में यह स्पष्ट किया कि किसी भी तरह का दबाव या आरोप उन्हें अपने काम करने की दिशा में विचलित नहीं कर सकता। उनका ध्यान केवल संसद में जनहित के मुद्दों को उठाने और सरकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने पर है।

साथ ही, चड्ढा ने यह भी उल्लेख किया कि विपक्ष के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने हमेशा संवैधानिक और नियमों के अनुसार काम किया है। उन्होंने कहा कि संसद में उनकी सक्रियता हमेशा जनहित में रही है, चाहे वह जीएसटी और आयकर के मुद्दे हों, दिल्ली और पंजाब में पर्यावरण और जल संबंधी समस्याएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी नीतियां या बेरोजगारी और महंगाई जैसी सामाजिक समस्याएं।

थलपति विजय का चुनावी मास्टरस्ट्रोक: पुदुचेरी में मुफ्त बिजली और 25 लाख का बीमा का वादा

पुदुचेरी। आगामी नौ अप्रैल को होने वाले पुदुचेरी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर क्षेत्र में राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस बार सियासी रंगमंच पर एक नया मोड़ तब आया जब दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार और टीवीके पार्टी के प्रमुख थलपति विजय ने एक भव्य चुनावी रैली में मतदाताओं के सामने अपने शासन और विकास एजेंडे का पूरा खाका पेश किया। विजय ने कांग्रेस-डीएमके गठबंधन को 'भ्रमित गठबंधन' करार देते हुए विपक्ष के रणनीति और उनकी नीतियों पर तीखा प्रहार किया। वहीं, एनआर कांग्रेस-भाजपा गठबंधन को 'थका हुआ गठबंधन' बताते हुए उन्होंने कहा कि दोनों राष्ट्रीय दल वर्षों तक केंद्र में सत्ता में रहने के बावजूद पुदुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में नाकाम रहे।

रैली में विजय ने मतदाताओं से आग्रह किया कि वे टीवीके के चुनाव चिन्ह का समर्थन करें। उन्होंने इसे 'एक उंगली की क्रांति' बताया, जो उनके फैंस के लिए किसी फिल्मी डायलॉग से प्रेरित प्रतीत होता है। विजय ने स्पष्ट किया कि उनका अभियान केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है बल्कि यह पुदुचेरी के लिए

वास्तविक और स्थायी विकास सुनिश्चित करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सत्ता में आने के छह महीने के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराएगी, जिससे जनता सीधे प्रशासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। विजय ने पुदुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आने पर उपराज्यपाल के हस्तक्षेप से मुक्त करते हुए कानूनी रूप से पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। यह वादा पुदुचेरी के मतदाताओं के लिए एक मजबूत संकेत है कि टीवीके पार्टी राज्य की स्वायत्तता और स्थानीय प्रशासन की मजबूती पर विशेष ध्यान देगी।

विकास और जनकल्याण पर भी विजय ने जोर दिया। उन्होंने घोषणा की कि उनकी सरकार सत्ता में आने पर हर परिवार के लिए 25 लाख रुपये का चिकित्सा बीमा उपलब्ध कराएगी। यह कदम न केवल क्षेत्र में स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगा बल्कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए भी राहत का स्रोत बनेगा। इसके अलावा उन्होंने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली की व्यवस्था करने का वादा किया। यह योजना सीधे रोजमर्रा के जीवन में लोगों की समस्याओं का समाधान करेगी और उनकी जीवनशैली में सुधार लाएगी। शिक्षा और क्षेत्रीय विकास पर भी विजय ने विशेष ध्यान दिया। उन्होंने पुदुचेरी विश्वविद्यालय ऑफ एप्लाइड साइंसेज एंड आर्ट्स की स्थापना की घोषणा की, जो राज्य के युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के नए अवसर खोलेगी। इसके माध्यम से क्षेत्र के छात्रों को आधुनिक तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे रोजगार और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। विजय ने मतदाताओं से इस विश्वविद्यालय को भविष्य के विकास की नींव के रूप में देखने की अपील की। विजय ने गठबंधन राजनीति पर भी तीखे वार किए। उन्होंने राष्ट्रीय दलों पर आरोप लगाया कि उन्होंने राज्य के विकास की अनदेखी की और केवल चुनावी राजनीति में उलझे रहे। उन्होंने क्षेत्रीय दलों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि स्थानीय नेतृत्व और स्थानीय नीतियां ही जनता के वास्तविक हितों की रक्षा कर सकती हैं। उनके इस बयान से राज्य में राजनीतिक हलचल और बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर विपक्ष के गठबंधन और उनकी रणनीतियों को चुनौती दी। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि विजय का यह कदम केवल चुनावी घोषणाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह पुदुचेरी के मतदाताओं के बीच विश्वास और उत्साह बढ़ाने का प्रयास है। मुफ्त बिजली, उच्च बीमा सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश के वादे सीधे जनता के रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हुए हैं, जो टीवीके पार्टी के पक्ष में मतदाताओं की सहमति को मजबूत कर सकते हैं।

केरल की सियासी बवंडर: माकपा के बागी सुधाकरण ने राहुल गांधी के साथ साझा किया मंच, सीएम विजयन की छवि चुनौती में

तिरुवनंतपुरम। केरल की राजनीति में इन दिनों वह परिस्थितियाँ बन रही हैं जो किसी सिनेमा की कहानी में दिखाई जाती हैं। राज्य की वामपंथी राजनीति के सबसे मजबूत किलों में से एक अलप्पुझा में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आया है, जिसने तिरुवनंतपुरम और राज्य की सत्ता गलियारों में हलचल मचा दी है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआईएम) के वरिष्ठ नेता जी सुधाकरण ने पार्टी की अनुशासित पंक्ति से अलग होकर बगावत की राह पकड़ ली है। सुधाकरण ने सीधे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अपने लंबे राजनीतिक अनुभव के दम पर उनकी छवि को चुनौती दी।

राजनीतिक इतिहास और अनुभव के साथ सुधाकरण ने मंच पर स्पष्ट किया कि उनके पास 63 वर्षों का पार्टी अनुभव है। उन्होंने कहा कि जब वे 15 वर्ष के थे, तब से ही कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए हैं और वर्षों तक पार्टी के लिए जमीन पर काम करते रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री विजयन की तुलना अपने राजनीतिक सफर से करते हुए कहा कि 1967 के दशक में जब वह मेहनत और संघर्ष कर रहे थे, तब विजयन का नाम केवल मालाबार के थालास्सेरी तक ही सीमित था और त्रावणकोर या दक्षिण केरल में उन्हें कोई जानता तक नहीं था। सुधाकरण की यह टिप्पणी पार्टी और मुख्यमंत्री के भीतर गहरी हलचल पैदा कर रही है।

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस राजनीतिक बगावत में सुधाकरण ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के साथ मंच साझा किया। राहुल गांधी ने इस अवसर का पूरा फायदा उठाते हुए सुधाकरण का स्वागत किया और मंच से कहा कि आज वामपंथ अपनी मूल विचारधारा और संगठनात्मक मजबूती खो चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि सुधाकरण जैसे अनुभवी और सच्चे नेताओं को अब कांग्रेस और यूडीएफ के साथ जुड़ना पड़ रहा है। यह संकेत है कि राज्य में आगामी चुनाव में वामपंथ के अंदर मतभेद और संगठनात्मक कमजोरियाँ कांग्रेस के पक्ष में काम कर सकती हैं।

2021 के विधानसभा चुनाव में माकपा ने सुधाकरण को किनारे कर दिया था, जिसके बाद वह राजनीति में अपेक्षाकृत शांत रहे। लेकिन चुनाव से ठीक पहले उन्होंने निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इस कदम के तुरंत बाद कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ ने उन्हें समर्थन देने की घोषणा की। इस समर्थन ने अलप्पुझा की चुनावी जंग को रोमांचक बना दिया है, क्योंकि यहाँ का मतदाताओं का समीकरण पहले से ही जटिल रहा है और सुधाकरण की प्रतिष्ठा ने इसमें और भी संवेदनशीलता जोड़ दी है।

सुधाकरण केवल राजनीतिक आरोप तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने व्यक्तिगत और भावुक मुद्दों को भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि विजयन के नेतृत्व वाली माकपा ने उनके शहीद भाई की कानूनी लड़ाई में परिवार का साथ नहीं दिया। उन्हें न्याय की लड़ाई खुद अपने संसाधनों से लड़नी पड़ी। इस बात ने उनके व्यक्तित्व को संवेदनशील और न्यायप्रिय नेता के रूप में प्रस्तुत किया, जो केवल राजनीतिक लाभ के लिए कदम नहीं उठा रहे, बल्कि अपने और अपने परिवार के अधिकारों के लिए भी संघर्षरत हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सुधाकरण की बगावत केवल अलप्पुझा या केरल तक सीमित नहीं रहेगी। यह राज्य की वामपंथी राजनीति में लंबी समय तक प्रभाव डाल सकती है। माकपा के भीतर नेतृत्व और अनुशासन के मुद्दे पहले ही चर्चा का विषय थे, और सुधाकरण की स्थिति ने पार्टी के भीतर विद्रोह की संभावनाओं को और स्पष्ट कर दिया है। यह परिवर्तन न केवल आगामी विधानसभा चुनावों को प्रभावित कर सकता है, बल्कि भविष्य में राज्य के राजनीतिक समीकरणों में भी बदलाव ला सकता है।

कांग्रेस और यूडीएफ के लिए यह स्थिति अवसर प्रदान करती है। सुधाकरण का समर्थन उनके गठबंधन को अलप्पुझा में मजबूती प्रदान करेगा और पार्टी की छवि को विस्तार देने में मदद करेगा। राहुल गांधी का मंच पर सक्रिय स्वागत और उनका संदेश कि वामपंथ अपनी मजबूती खो चुका है, यह संकेत देता है कि कांग्रेस के लिए इस चुनाव में सुधाकरण के सहयोग से राजनीतिक लाभ संभावित है।

सुधाकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत विरोध नहीं है। उन्होंने पार्टी की नीतियों, नेतृत्व के निर्णयों और कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। उनकी आलोचना ने यह साबित किया कि राज्य की सियासत में व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और अनुभव अब भी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। इससे मुख्यमंत्री विजयन की छवि पर सवाल उठे हैं, क्योंकि पार्टी के भीतर वरिष्ठ नेताओं का असंतोष सत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार, सुधाकरण की भूमिका केवल चुनावी रणनीति तक सीमित नहीं रहेगी। यह कदम राज्य की वामपंथी राजनीति में लंबे समय तक चर्चा का विषय रहेगा। युवा नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच सुधाकरण का उदाहरण प्रेरणा और विवाद दोनों का स्रोत बन सकता है। यह बदलाव के संकेत हैं और राज्य में राजनीतिक स्थिरता को चुनौती दे सकते हैं।

इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट होता है कि केरल में चुनावी माहौल पहले से अधिक गर्म और अनिश्चित हो गया है। सुधाकरण के नेतृत्व में बागी खेमे का सक्रिय होना, कांग्रेस और यूडीएफ के साथ उनका गठबंधन और मुख्यमंत्री विजयन पर सीधे आरोप ने राजनीतिक गतिशीलता को बढ़ा दिया है। आगामी चुनावों में यह स्थिति मतदाताओं के निर्णय और चुनावी नतीजों पर बड़ा असर डाल सकती है।

सुधाकरण का यह कदम राज्य में राजनीतिक चेतना और मतदाता जागरूकता को भी बढ़ा सकता है। उनके अनुभव, संघर्ष और व्यक्तिगत न्याय की लड़ाई ने उन्हें केवल राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि जनता के बीच एक न्यायप्रिय और सिद्धांतवादी नेता के रूप में प्रस्तुत किया है। यह घटना यह भी संकेत देती है कि केरल की राजनीति में व्यक्तित्व, अनुभव और न्याय के मुद्दे अब भी मतदाताओं के लिए निर्णायक हो सकते हैं।

इस प्रकार, केरल की सियासत में सुधाकरण की बगावत ने राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है। यह केवल चुनावी लड़ाई नहीं है, बल्कि राज्य की राजनीतिक संस्कृति, नेतृत्व शैली और विचारधारा की दिशा बदलने की कोशिश भी है। मुख्यमंत्री विजयन और माकपा के लिए यह चुनौती गंभीर है, जबकि कांग्रेस और यूडीएफ के लिए यह अवसर है। आगामी महीनों में यह देखना रोचक होगा कि अलप्पुझा और अन्य क्षेत्रों में मतदाताओं की प्रतिक्रिया क्या होगी और यह राज्य की राजनीति को किस दिशा में ले जाएगी।

गरवी गुजरात
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2002

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
गरवी गुजरात हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

बंगाल में अराजकता

पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत निर्वाचन नामावलियों के निस्तारण में लगे, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारियों को नौ घंटे तक बंधक बनाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण ही है। इन सात बंधक अधिकारियों में तीन महिलाएं भी शामिल थीं जिन्हें नौ घंटे तक बिना खाना-पानी के रोके रखा गया। स्वाभाविक रूप से इस घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव व डीजीपी समेत कई उच्च अधिकारियों का कारण बताओ नोटिस भी दिए हैं। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सात अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। पिछले महीने तक साठ लाख में 47 लाख आपत्तियों का निस्तारण होने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संतुष्टि व्यक्त की है। बहरहाल, इसके बावजूद एसआईआर प्रक्रिया को लेकर किसी व्यक्ति को कोई शिकायत है तो उसका निस्तारण निर्धारित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। बहरहाल, मालदा का यह घटनाक्रम कानून व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं के लिए भी अग्निपरीक्षा है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने पश्चिम बंगाल को राजनीतिक रूप से ध्रुवीकृत तथा चुनाव आयोग ने राज्य में जंगलराज होने की बात कही है। ध्यान रहे कि इससे पहले भी निर्वाचन अधिकारियों से मारपीट व घेराव की घटनाएं सामने आई हैं। जाहिर बात है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कुछ लोगों में असंतोष है। मतदाता सूची से नाम कटने वाले लोगों की तल्ख प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। लेकिन यह तंत्र के प्रति बढ़ते अविश्वास का भी प्रतीक है, जिसके चलते ही घटनाक्रम के बाद सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने पश्चिम बंगाल में इस महीने होने वाले चुनाव से पहले कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। अब राज्य में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल में इस माह की 23 व 29 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में मालदा का घटनाक्रम निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए चुनौती दर्शाने वाला है।

बहरहाल, मालदा के कालियाचक में भीड़ द्वारा अभिव्यक्त आक्रोश और न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने का घटनाक्रम यह बताता है कि लोगों में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर व्यापक असंतोष है। यद्यपि कानून व्यवस्था को हाथ में लेना कदापि उचित नहीं कहा जा सकता है, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा पहले ही घटना का आकलन न कर पाना और समय रहते कार्रवाई न करना, तंत्र की विफलता को ही दर्शाता है। जिसे कानून व्यवस्था की नाकामी ही कहा जा सकता है। जब राज्य में एसआईआर काम में लगे लोगों को पहले से लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा था, तो इस कार्य में लगे न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था की जानी चाहिए थी। लोगों में उपजे अविश्वास के मद्देनजर इस दिशा में सतर्क पहल जरूरी थी। इसमें दो राय नहीं कि पश्चिम बंगाल में व्यापक पैमाने पर विदेशियों की घुसपैठ की समस्या रही है। ऐसे में एसआईआर प्रक्रिया द्वारा मतदाताओं की पड़ताल राष्ट्रीय सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन जटिल प्रक्रिया के चलते व जरूरी कागजों के उपलब्ध न होने से कुछ वैध मतदाताओं को अपनी वैधता की पुष्टि के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चिंताओं को भी समझने की जरूरत है। ऐसे मतदाताओं के अविश्वास को भी दूर करने की जरूरत है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट इस प्रक्रिया पर शुरू से ही नजर बनाये हुए है। चुनाव आयोग भी दावा कर रहा है कि किसी योग्य मतदाता के साथ अन्याय नहीं होगा। इसी मकसद से ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया पर निगरानी के मकसद से न्यायिक अधिकारियों की तैनाती की थी। लेकिन विडंबना है कि उन्हें ही आक्रोशित भीड़ ने बंधक बनाया। लेकिन इसके बावजूद सरकारी तंत्र को लोगों के बीच भरोसा कायम करने का प्रयास करना चाहिए। विश्वास किया जाना चाहिए कि राज्य के राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर राजनीति करने के बजाय मतदाताओं को तर्कपूर्ण ढंग से स्वतंत्र व पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिये प्रेरित करेंगे। राज्य में स्वतंत्र-निष्पक्ष तथा पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए राजनेताओं का संवेदनशील व्यवहार जरूरी है।

पश्चिम बंगाल में बढ़ती अराजकता लोकतंत्र के लिए

> "नागरिक समाज सक्रिय रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आगे नहीं आएगा, तब तक केवल प्रशासनिक उपायों से इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें कानून का शासन, संस्थाओं की स्वतंत्रता और नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है।

पश्चिम बंगाल, जो कभी सांस्कृतिक चेतना, बौद्धिकता और राजनीतिक परिपक्वता का प्रतीक माना जाता था, आज एक ऐसे संक्रमणकाल से गुजर रहा है, जहां लोकतांत्रिक मूल्यों की जड़ें लगातार कमजोर होती प्रतीत हो रही हैं। जैसे-जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे-वैसे राज्य में हिंसा, अराजकता अलोकतांत्रिकता और राजनीतिक असहिष्णुता की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यह केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का परिणाम नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति घटते सम्मान और कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति का भी द्योतक है। हाल ही में मालदा जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण अर्थात एसएआर को लेकर जिस प्रकार का असंतोष और तनाव देखने को मिला, वह भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति अविश्वास को दर्शाता है। मतदाता सूची में नाम जुड़ना या हटना एक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसके लिए स्पष्ट नियम और प्रावधान होते हैं। यदि इस प्रक्रिया को राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा या प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाया जाएगा, तो निष्पक्ष चुनाव की पूरी प्रक्रिया ही संदिग्ध हो जाएगी। एसएआर प्रक्रिया में बाधक बनते हुए जिसे तरह से न्यायिक अधिकारियों को नौ घंटे तक बंधक बनाए जाने की घटना सामने आयी है, वह न केवल चिंताजनक है बल्कि लोकतंत्र के लिये एक गंभीर चेतावनी भी है। यह उस व्यापक घातक एवं विडम्बनापूर्ण प्रवृत्ति का हिस्सा है, जिसमें प्रशासनिक और न्यायिक तंत्र को भी राजनीतिक दबाव और भीड़तंत्र के आगे झुकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। विशेष रूप से यह तथ्य कि बंधक बनाए गए अधिकारियों में महिलाएं भी शामिल थीं, इस घटना को और अधिक गंभीर बना देता है। यह न केवल कानून के शासन पर प्रश्नचिह्न लगाता है, बल्कि समाज में बढ़ती असंवेदनशीलता को भी उजागर करता है।पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास नया नहीं है। 1960 और 70 के दशक में नक्सल आंदोलन के दौरान हिंसा का जो दौर शुरू हुआ था, उसने राज्य की राजनीतिक संस्कृति को गहराई

से प्रभावित किया। इसके बाद वामपंथी शासन के लंबे कालखंड में भी राजनीतिक विरोधियों के प्रति असहिष्णुता और हिंसा की घटनाएं समय-समय पर सामने आती रहीं। सत्ता परिवर्तन के बाद तृणमूल कांग्रेस एवं ममता बनर्जी के शासन में यह प्रवृत्ति समाप्त नहीं हुई, बल्कि नए स्वरूप में सामने आई। यह स्पष्ट संकेत है कि समस्या केवल किसी एक दल या विचारधारा की नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र में व्याप्त एक गहरे संकट की है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, चुनावों के निकट आते ही जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, वे लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरे का संकेत देती हैं। मतदाता सूची के पुनरीक्षण जैसे संवेदनशील कार्य में लगे अधिकारियों को बंधक बनाना यह दर्शाता है कि कुछ तत्व चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि मतदाता की स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव के अधिकार पर सीधा हमला है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता उल्लेखनीय है। समय-समय पर न्यायालय ने राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी की याद दिलाई है। किंतु यह भी एक चिंताजनक तथ्य है कि इन निर्देशों का जमीनी स्तर पर अपेक्षित प्रभाव नहीं दिखाई देता। इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या राज्य प्रशासन एवं सत्तारूढ पार्टी इन निर्देशों को लागू करने में अक्षम है या इच्छुक नहीं है? यदि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश भी प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं, तो यह लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चेतावनी है। चुनाव के समय बढ़ती अराजकता के पीछे राजनीतिक बौखलाहट भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकती है। जब किसी दल को अपनी लोकप्रियता में गिरावट का भय होता है, तो वह अक्सर लोकतांत्रिक मर्यादाओं को दरकिनार कर असंवैधानिक उपायों का सहारा लेने लगता है। पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसी ही प्रवृत्तियां देखने को मिल रही हैं, जहां सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं पर विपक्ष को डराने, प्रशासनिक कार्यों में बाधा डालने और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लगते रहे हैं। यदि इन आरोपों में सच्चाई है, तो यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विपरीत है।

नागरिक समाज सक्रिय रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आगे नहीं आएगा, तब तक केवल प्रशासनिक उपायों से इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें कानून का शासन, संस्थाओं की स्वतंत्रता और नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति इन सभी पहलुओं पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। यदि चुनाव प्रक्रिया ही निष्पक्ष और शांतिपूर्ण नहीं रह जाती, तो लोकतंत्र का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति मतदाता का विश्वास होता है, और यदि मतदाता को यह लगने लगे कि मतदाता सूची, चुनाव प्रक्रिया या प्रशासन किसी राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है, तो लोकतंत्र की विश्वसनीयता स्वतः कमजोर होने लगती है। इस पूरे घटनाक्रम में प्रशासनिक नाकामी का प्रश्न भी गंभीरता से सामने आता है। किसी भी राज्य में यदि अधिकारी सुरक्षित नहीं हैं, न्यायिक अधिकारी तक बंधक बना लिए जाते हैं और पुलिस या प्रशासन समय पर प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाता, तो यह प्रशासनिक तंत्र की कमजोरी का स्पष्ट प्रमाण है। प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखना और सरकारी कार्यों को निर्भय वातावरण में संपन्न कराना होता है। यदि प्रशासन यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है, तो इससे जनता में भय और अविश्वास दोनों बढ़ते हैं। जनता का विश्वास ही किसी सरकार की सबसे बड़ी पूंजी होता है, और जब यही विश्वास डगमगाने लगता है, तो शासन की वैधता पर भी प्रश्नचिह्न लगने लगते हैं।

राजनीतिक दलों की भूमिका भी इस पूरे परिदृश्य में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं होते, बल्कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों के संवाहक भी होते हैं। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्यकर्ताओं को संयम, कानून के सम्मान और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करने के लिए प्रेरित करें। लेकिन जब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कटु संघर्ष में बदल जाती है और कार्यकर्ताओं को किसी भी तरह से राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि राजनीतिक दल चुनाव को युद्ध नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक उत्सव के रूप में देखें। आज आवश्यकता इस बात की है कि पश्चिम बंगाल की घटनाओं को केवल एक राज्य की समस्या न मानकर लोकतंत्र के लिए चेतावनी के रूप में देखा जाए। यदि प्रशासनिक तंत्र कमजोर होगा, राजनीतिक दल मर्यादा नहीं रखेंगे, और जनता का विश्वास कम होता जाएगा, तो लोकतंत्र केवल कागजों तक सीमित रह जाएगा। लोकतंत्र की रक्षा केवल संविधान या न्यायालय नहीं कर सकते, इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक निष्पक्षता और जनता की जागरूकताकृतीनों का संतुलन आवश्यक है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान परिस्थितियां हमें यही संदेश देती हैं कि लोकतंत्र को केवल चुनाव से नहीं, बल्कि व्यवस्था की निष्पक्षता, कानून के शासन और नागरिक विश्वास से मजबूत बनाया जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है कि राज्य सरकार, चुनाव आयोग और न्यायपालिका मिलकर ठोस कदम उठाएं। कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाए, दोषियों के खिलाफ त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई हो और प्रशासनिक तंत्र को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखा जाए। इसके साथ ही राजनीतिक दलों को भी आत्ममंथन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कार्यकर्ता लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करें। निश्चित ही यह समझना होगा कि लोकतंत्र की रक्षा केवल संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति एक चेतावनी है कि यदि समय रहते सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो यह अराजकता और गहराई तक फैल सकती है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है कि हम सभी मिलकर कानून, नैतिकता और सहिष्णुता के मूल्यों को पुनः स्थापित करें। पश्चिम बंगाल आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां से वह या तो लोकतांत्रिक पुनर्जागरण की ओर बढ़ सकता है या अराजकता के गहरे गर्त में गिर सकता है। यह निर्णय न केवल राजनीतिक नेतृत्व, बल्कि पूरे समाज को मिलकर लेना होगा।

प्रेरणा

सत्ता से ऊपर कर्तव्य: सच्ची राष्ट्रभक्ति की अमर गाथा

मानव इतिहास में ऐसे व्यक्तित्व बहुत कम मिलते हैं, जिन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया हो कि सच्ची महानता सत्ता, वैभव या प्रतिष्ठा में नहीं, बल्कि कर्तव्यनिष्ठा और त्याग में निहित होती है। लूसियस क्विनक्टियस सिनसिनाटस का जीवन इसी आदर्श का जीवंत उदाहरण है। उनकी कहानी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि यह एक ऐसा संदेश है जो हर युग में समाज और नेतृत्व को दिशा देने का कार्य करता है।

सिनसिनाटस एक साधारण किसान थे, जिनका जीवन अत्यंत सादा और श्रमपूर्ण था। वे अपने खेतों में मेहनत करते, प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीते और किसी प्रकार की सत्ता या विलासिता की इच्छा नहीं रखते थे। उनका जीवन यह दर्शाता है कि सच्चा संतोष बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाने में होता है। वे अपने परिवार और भूमि से जुड़े हुए थे, और यही उनका वास्तविक संसार था।

लेकिन जब रोमन गणराज्य पर संकट आया, तब परिस्थितियाँ बदल गईं। शत्रु सेना ने राज्य को घेर लिया और स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि तत्काल एक सक्षम और निस्वार्थ नेतृत्व की आवश्यकता महसूस हुई। उस समय रोमन सीनेट ने सिनसिनाटस को याद किया। यह निर्णय इस बात का प्रमाण था कि समाज में उनकी छवि एक ईमानदार, निडर और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की थी।

जब दूत उनके पास पहुँचे, तब वे अपने खेत में हल चला रहे थे। यह दृश्य अपने आप में बहुत गहरा संदेश देता है। एक ओर राज्य का संकट था और दूसरी ओर एक व्यक्ति जो पूरी तन्मयता से अपने श्रम में लगा हुआ था। जैसे ही उन्हें स्थिति के बारे में बताया गया, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना कार्य छोड़ दिया और राज्य की सेवा के लिए तैयार हो गए। यह निर्णय बताता है कि उनके लिए व्यक्तिगत जीवन से ऊपर राष्ट्र का कर्तव्य था।

सिनसिनाटस ने सत्ता को कभी लक्ष्य नहीं माना, बल्कि उसे केवल एक माध्यम के रूप में देखा। जब उन्होंने शासक का पद स्वीकार किया, तो उनके मन में न कोई अहंकार था और न ही किसी प्रकार का स्वार्थ। उनका एकमात्र उद्देश्य था—राज्य को संकट से बचाना। उन्होंने सेना का नेतृत्व किया, अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचय दिया और शत्रुओं को पराजित किया। यह विजय केवल युद्ध की जीत नहीं थी, बल्कि यह सिद्धांतों और मूल्यों की जीत भी थी।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विजय के बाद उनके पास अपार शक्ति थी। वे चाहें तो लंबे समय तक सत्ता में बने रह सकते थे, अपने लिए सुविधाएँ जुटा सकते थे और इतिहास में एक शक्तिशाली शासक के रूप में स्थान बना सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने स्वेच्छा से सत्ता का त्याग किया और अपने खेतों की ओर लौट गए। यह निर्णय उनके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता को उजागर करता है—निस्वार्थता।

आज के समय में जब सत्ता को अक्सर व्यक्तिगत लाभ और प्रतिष्ठा के साधन के रूप में देखा जाता है, सिनसिनाटस का यह उदाहरण अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्चा नेता वही होता है जो आवश्यकता पड़ने पर जिम्मेदारी निभाए और कार्य पूरा होने के बाद बिना किसी मोह के पीछे हट जाए। यह गुण अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि सत्ता का आकर्षण बहुत प्रबल होता है।

उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि राष्ट्रभक्ति केवल बड़े-बड़े भाषणों या दिखावे से नहीं होती, बल्कि यह एक आंतरिक भावना होती है। जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र के लिए कार्य करता है, तभी वह सच्चा देशभक्त कहलाता है। सिनसिनाटस ने अपने कार्यों से यह सिद्ध किया कि देशभक्ति का अर्थ है—कर्तव्य का पालन, ईमानदारी और त्याग। उनकी कहानी में एक और महत्वपूर्ण संदेश छिपा है—संतुलन का। उन्होंने अपने जीवन में व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच एक अद्भुत संतुलन बनाए रखा। जब आवश्यकता थी, तब उन्होंने समाज के लिए कार्य किया, और जब संकट समाप्त हो गया, तब वे पुनः अपने निजी जीवन में लौट गए। यह संतुलन आधुनिक जीवन में अत्यंत आवश्यक है, जहाँ लोग अक्सर एक पक्ष को निभाते हुए दूसरे को नजरअंदाज कर देते हैं।

सिनसिनाटस का जीवन यह भी दर्शाता है कि सच्ची प्रतिष्ठा और सम्मान सत्ता से नहीं, बल्कि चरित्र से मिलता है। आज भी उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में उन मूल्यों को जिया, जिनकी अपेक्षा हर समाज अपने नेताओं से करता है। उन्होंने यह साबित किया कि महानता का मापदंड व्यक्ति की स्थिति नहीं, बल्कि उसके निर्णय और आचरण होते हैं।

उनकी कहानी हमें आत्मचिंतन के लिए भी प्रेरित करती है। क्या हम अपने जीवन में अपने कर्तव्यों को उतनी ही निष्ठा से निभाते हैं? क्या हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के बारे में सोचते हैं? क्या हम सफलता मिलने पर भी विनम्र बने रहते हैं? ये प्रश्न हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यही वह आधार हैं, जिन पर एक मजबूत और नैतिक समाज का निर्माण होता है।

अंततः, लूसियस क्विनक्टियस सिनसिनाटस का जीवन एक प्रकाशस्तंभ की तरह है, जो हमें यह दिखाता है कि सच्ची शक्ति त्याग में है, सच्ची महानता सादगी में है और सच्ची राष्ट्रभक्ति कर्तव्य में है। उनका उदाहरण हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी ऊँचाई क्यों न प्राप्त हो जाए, हमें अपने मूल्यों और सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए।

आज के दौर में जब दुनिया तेजी से बदल रही है और मूल्य धीरे-धीरे कमजोर पड़ते जा रहे हैं, ऐसे में सिनसिनाटस जैसे व्यक्तित्व हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा विकास केवल भौतिक प्रगति में नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति में भी होता है। उनका जीवन एक प्रेरणा है—एक ऐसा आदर्श, जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है।

नौकरी के लिए न्यूनतम अंक भी प्राप्त नहीं होना अध्ययन गुणवत्ता पर उठाते सवाल

अभी मेडिकल पीजी में 0 पर्सेंटाइल पर प्रवेश का मुद्दा पुराना भी नहीं हुआ है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा स्कूल लेक्चरर के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम ने देश की शिक्षा के हालातों के पोल खोलकर ही रख दी है। शिक्षा के मंदिर में बच्चों को पढ़ाने के लिए लेक्चरर के पद पर नियुक्ति के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में पोलिटिकल साइंस के लेक्चरर के पद के लिए हजारों युवाओं ने परीक्षा दी और 225 पद होने के बावजूद केवल 6 परीक्षार्थी चयन के योग्य पाये गये। मजे की बात है कि परीक्षा देने वाले हजारों युवाओं में मात्र 219 युवा भी न्यूनतम प्राप्तांक 40 प्रतिशत अंक भी प्राप्त नहीं कर पायें। हालात की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि फिजिकल एजुकेशन के 37 पदों के लिए एक भी नहीं और होमसाइंस जैसे विषय के लेक्चरर के पद के लिए केवल एक परीक्षार्थी ही सफल हो सका। अब एक और देश में प्रतिपक्ष बेरोजगारी की समस्या को गंभीरता से उठा रहे हैं तो दूसरी और भर्ती वाले पदों के लिए न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करने में भी आज के युवा सफल नहीं हो पा रहे हैं। यह कोई राजस्थान की ही बात नहीं है अपितु यह समूचे देश की शिक्षा के स्तर की बानगी है। क्योंकि निश्चित रुप से राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अन्य प्रदेशों के युवा भी परीक्षार्थी रहे होंगे। बेरोजगारी की समस्या अपनी जगह पर है पर दूसरी और स्नातक, स्नातकोत्तर और तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं के ज्ञान के स्तर को इससे आंका जा सकता है। यही कारण है कि आज मल्टी टास्क सर्विस जिसे परपंरागत शब्दों में कहा जाए तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद या शहरी निकायों में सफाई कर्मचारी के कुछ पदों के लिए ही हजारों लाखों युवा आवेदन करने लगे हैं और तस्वीर का एक पहलू यह है कि इन युवाओं में उच्च और तकनीकी शिक्षा यहां तक की इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीए तक आवेदन कर रहे हैं। यह हमारे शैक्षणिक संस्थानों के लिए किसी तमाचे से कम नहीं होना चाहिए। अब पोलिटिकल साइंस के स्कूल लेक्चरर के लिए परीक्षा देने वाले युवा निश्चित रुप से पोलिटिकल साइंस से स्नातक या स्नातकोत्तर और हो सकता है कि पीएच डी तक हो पर उनके द्वारा केवल और केवल न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक भी प्राप्त नहीं करना कहीं ना कहीं शिक्षा की स्थिति को स्पष्ट करती है। वैसे देखा जाएं तो 40 प्रतिशत अंक प्राप्त कर चयनित होने वाले स्कूल लेक्चरर से आप बच्चों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की अपेक्षा करेंगे तो बेमानी होगी। हालात वास्तव में गंभीर है और यही कारण है कि नौकरी के लिए आयोजित परीक्षाओं में नकल, गलत प्रयोग और पेपर आउट व डमी केंडिडेट द्वारा परीक्षाएं देने के माफियाओं की बन पड़ी है।

जहां तक मेडिकल पीजी में जीरो पर्सेंटाइल पर प्रवेश के निर्णय पर यह अवश्य संतोष की बात है कि फैडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार के इस निर्णय की खिलाफत करने की हिम्मत दिखाई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि देष में षिक्षण संस्थाओं का जाल बिछा कर सबके लिए शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो सकी। अब तो डीम्ड यूनिवर्सिटी सहित यूनिवर्सिटी नित नई खुलती जा रही है। इसे अच्छा भी माना जा सकता है पर सौ टके का सवाल यह है कि क्या शिक्षण संस्थान केवल डिग्री देने के माध्यम ही बन कर रह गए हैं।

पोलिटिकल साइंस स्कूल लेक्चरर या अन्य पदों के लिए न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने वाली युवाओं की पीढ़ी तैयार हो रही है तो इसके लिए सबसे अधिक शर्म की बात इन शिक्षण संस्थानों के लिए होनी चाहिए। पोलिटिकल साइंस तो उदाहरण मात्र है, सवाल यह है कि परीक्षा देने वाले हजारों प्रतियोगी किसी एक संस्थान से तो डिग्री प्राप्त नहीं होंगे। मजे और शर्म की बात यह है कि इन हजारों प्रतियोगी छात्रों में से कई युवा तो स्तरीयता का दावा करने वाले संस्थान के शिक्षार्थी रहे होंगे, उसके बाद नौकरी के लिए परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो इससे अधिक बुरी बात क्या होगी? आखिर हम जा कहां रहे हैं। शिक्षण संस्थानों की स्तरीयता पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा जिस तरह से कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरियों की बाढ़ आई हुई है उसके परिणाम भी इन परिणामों में कहीं दूर दूर तक लक्षित नहीं हो रहे। सरकार और तकनीकी शिक्षण संस्थानों को कम से कम अपने स्तर का तो ध्यान रखना ही होगा। शिक्षा की गुणवत्ता और तकनीकी अध्ययन की वैश्विक पहचान बनाना सरकार और अध्ययन केन्द्रों की पहली और अंतिम प्राथमिकता होनी चाहिए, पर यहां तो स्थानीय स्तर पर ही खरे नहीं उतर पा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि जीरो पर्सेंटाइल वालों को विशेषज्ञ बनाकर ईलाज का लाइसेंस देंगे तो यह आमनागरिकों की जिंदगी से खिलवाड़ और शिक्षा पद्धति को मजाक बनाना ही है। सरकार और आयोग को समय रहते शिक्षा के स्तर को बनाए रखने की पहल करनी होगी। इसी से देश की शिक्षा की गुणवत्ता देश दुनिया में बनी रह सकेगी। सरकारी और गैरसरकारी संस्थाओं को खासतौर से आगे आना होगा। हालात शिक्षण संस्थानों को शर्मिंदा करने के लिए काफी होने चाहिए। परिणाम एक बार युवाओं को तैयार कर रही इन संस्थानों के लिए भी आत्मचिंतन के होने चाहिए। परिणाम साफतौर पर इन संस्थानों को चेहरा दिखाते नजर आ रहे हैं।

अभियान

आस्था का दिव्य संकेत: चामुंडा देवी धाम की रहस्यमयी कथा और आध्यात्मिक महिमा

हिमाचल प्रदेश की शांत, सुरम्य और आध्यात्मिक वादियों में स्थित चामुंडा देवी धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह श्रद्धा, विश्वास और दिव्य चमत्कारों का जीवंत केंद्र है। धौलाधार पर्वतमाला की भव्यता और बनेर नदी के शांत प्रवाह के बीच स्थित यह मंदिर हर उस व्यक्ति को आकर्षित करता है, जो केवल पूजा नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और दिव्य अनुभव की तलाश में यहां आता है। इस धाम का इतिहास जितना पुराना है, उतना ही रहस्यमय भी है, और इसकी हर कथा भक्तों के मन में आस्था की नई ज्योति प्रज्वलित करती है।

चामुंडा देवी मंदिर का वर्तमान स्वरूप एक साधारण निर्माण की कहानी नहीं, बल्कि एक दिव्य संकेत का परिणाम है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में यह मंदिर धौलाधार पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटी पर स्थित था। उस समय वहां तक पहुंचना अत्यंत कठिन था। ऊंचे-ऊंचे पहाड़, घने जंगल और खतरनाक रास्ते भक्तों के लिए एक बड़ी चुनौती थे। फिर भी, सच्चे श्रद्धालु अपनी भक्ति के बल पर वहां तक पहुंचते थे। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, भक्तों की संख्या बढ़ने लगी और उनके लिए इस कठिन यात्रा को पूरा करना और भी मुश्किल होता गया।

तब उस क्षेत्र के राजा और एक श्रद्धालु पुजारी ने मिलकर देवी मां से प्रार्थना की कि वह अपने स्थान को ऐसी जगह पर स्थापित करने की अनुमति दें, जहां हर कोई आसानी से पहुंच सके। यह प्रार्थना केवल सुविधा के लिए नहीं थी, बल्कि यह एक सच्चे भक्त का निवेदन था, जिसमें जनकल्याण की भावना छिपी हुई थी। इस प्रार्थना का उत्तर देवी ने एक अद्भुत और रहस्यमय तरीके से दिया। एक रात पुजारी को स्वप्न में माता चामुंडा के दर्शन हुए। यह स्वप्न साधारण नहीं था, बल्कि एक दिव्य आदेश था। देवी ने पुजारी से कहा कि वह वर्तमान स्थान पर खुदाई करें, जहां उनकी मूर्ति छिपी हुई है। इस स्वप्न की स्पष्टता और शक्ति इतनी प्रबल थी कि पुजारी ने इसे मात्र कल्पना नहीं समझा, बल्कि इसे देवी का साक्षात आदेश मान लिया। अगले ही दिन उन्होंने यह बात राजा को बताई और दोनों ने मिलकर उस स्थान पर खुदाई शुरू करवाई।

जैसे-जैसे खुदाई आगे बढ़ती गई, लोगों की उत्सुकता भी बढ़ती गई। अंततः वह क्षण आया, जब धरती के गर्भ से माता की दिव्य मूर्ति प्रकट हुई। यह दृश्य वहां उपस्थित सभी लोगों के लिए एक चमत्कार से कम नहीं था। ऐसा लगा मानो स्वयं देवी ने अपनी उपस्थिति का संकेत दिया हो और यह बताया हो कि यह स्थान उनका चुना हुआ स्थान है।

लेकिन इस चमत्कार के साथ एक और रहस्य जुड़ा हुआ था। जब राजा के सैनिकों ने उस मूर्ति को उठाने का प्रयास किया, तो वे असफल रहे। चाहे जितनी भी शक्ति लगाई गई, मूर्ति अपने स्थान से हिली तक नहीं। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। तब पुजारी को फिर से स्वप्न में देवी के दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि इस मूर्ति को केवल वही व्यक्ति स्थापित कर सकता है, जिसे उन्होंने स्वयं चुना है।

देवी के निर्देश के अनुसार, पुजारी ने स्वयं उस मूर्ति को उठाया और उसे वर्तमान स्थान पर स्थापित किया। यह घटना इस बात का प्रमाण मानी जाती है कि देवी की इच्छा के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं होता। इस प्रकार चामुंडा देवी मंदिर का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया और यह स्थान धीरे-धीरे लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र बन गया।

इस मंदिर की एक और विशेषता है इसके पीछे स्थित प्राकृतिक गुफा, जिसे शिव और शक्ति का संयुक्त निवास स्थान माना जाता है। इस गुफा में नंदीकेश्वर महादेव का शिवलिंग स्थापित है, जिसके दर्शन के लिए भक्त दूर-दूर से आते हैं। यह स्थान केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि साधना और ध्यान का केंद्र भी है। यहां का वातावरण इतना शांत और ऊर्जावान है कि कोई भी व्यक्ति यहां बैठकर ध्यान करता है, तो उसे एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव होता है।

इसी कारण इस धाम को चामुंडा नंदीकेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम स्वयं में शिव और शक्ति के अद्वैत स्वरूप का प्रतीक है। हिंदू दर्शन में शिव और शक्ति को एक ही तत्व के दो रूप माना गया है। जहां शक्ति सृजन और क्रिया की प्रतीक है, वहीं शिव चेतना और स्थिरता के प्रतीक हैं। इस गुफा में इन दोनों का संगम एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है।

मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही भक्तों का ध्यान माता चामुंडा की भव्य प्रतिमा की ओर आकर्षित होता है। उनके चेहरे पर एक साथ करुणा और शक्ति का अद्भुत मिश्रण दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो माता हर भक्त की पीड़ा को समझती हैं और उसे अपने आशीर्वाद से भर देती हैं। मंदिर के दोनों ओर भैरव जी और हनुमान जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं, जिन्हें माता के रक्षक और प्रतिनिधि के रूप में पूजा जाता है।

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, चामुंडा देवी का संबंध एक अत्यंत प्राचीन कथा से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि हजारों वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में चण्ड और मुण्ड नामक दो अत्यंत शक्तिशाली राक्षसों का आतंक था। वे निर्दोष लोगों को सताते थे और पूरे क्षेत्र में भय का वातावरण बना देते थे। तब देवी ने काली का उग्र रूप धारण किया और दोनों राक्षसों के साथ भीषण युद्ध किया।

यह युद्ध केवल एक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई का प्रतीक था। अंततः देवी ने चण्ड और मुण्ड का वध कर दिया और इस प्रकार इस क्षेत्र को उनके आतंक से मुक्त कराया। इसी विजय के कारण देवी को 'चामुंडा' नाम से जाना जाने लगा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब भी अधर्म अपनी सीमा पार करता है, तब दिव्य शक्ति किसी न किसी रूप में प्रकट होकर उसे समाप्त करती है।

चामुंडा देवी धाम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां आने वाला हर व्यक्ति केवल एक दर्शक बनकर नहीं जाता, बल्कि वह एक गहरी अनुभूति लेकर लौटता है। यहां की शांति, प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं, जो मन को भीतर तक छू जाता है। यह स्थान केवल पूजा का केंद्र नहीं, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण का भी स्थान है।

धौलाधार की ऊंची चोटियां, बनेर नदी का मधुर प्रवाह और मंदिर की घंटियों की गूंज—ये सभी मिलकर एक ऐसा दिव्य वातावरण बनाते हैं, जो किसी भी व्यक्ति को मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। यही कारण है कि यहां हर दिन हजारों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं और हर कोई अपने साथ एक नई ऊर्जा, विश्वास और आशा लेकर लौटता है।

यह मंदिर हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल बाहरी आडंबरों में नहीं, बल्कि हृदय की सच्चाई में होती है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से देवी की आराधना करता है, तो उसे किसी विशेष विधि या स्थान की आवश्यकता नहीं होती। देवी स्वयं उसके मार्ग को सरल बना देती हैं, जैसा कि इस मंदिर की स्थापना की कथा में देखने को मिलता है।

अंततः, चामुंडा देवी धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह एक जीवंत अनुभव है—एक ऐसा स्थान जहां आस्था और रहस्य एक साथ मिलकर जीवन के गहरे सत्य को उजागर करते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि जब श्रद्धा सच्ची होती है, तो स्वयं देवी मार्ग दिखाती हैं, चाहे वह स्वप्न के माध्यम से ही क्यों न हो। यही इस धाम का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ी शक्ति है, जो हर भक्त के हृदय में विश्वास की ज्योति को प्रज्वलित करती है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

सूरत में संगठन द्वारा विवादों का कानूनी समाधान, व्यापारियों को न्याय और सहायता प्रदान करने का एक अनूठा प्रयास है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सूरत शहर और गुजरात के बाहर के राज्यों में प्रवासी संरक्षण समिति और उपभोक्ता संरक्षण एवं अनुसंधान केंद्र के माध्यम से सेवाएं दी जा रही हैं। सूरत में, 25-30 साल पहले, उधना मेन रोड पर स्थित अरिहंत मिल के मालिक गजानंदजी मालपानी थे। शांतिलाल बाफना ने उनसे यह मिल किराए पर ली थी। कुछ समय तक मिल अच्छी तरह से चल रही थी। छपाई और रंगाई का काम चल रहा था, तय किराया समय पर दिया जा रहा था। एक दिन सुबह शांतिलाल बाफना और उनकी पत्नी सुबह की सैर पर निकले थे, तभी अचानक एक रेत और बजरी से भरे ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। इसके बाद, शांतिलालजी बाफना भातर चार रोड स्थित अपने घर में दिन-प्रतिदिन के मानसिक तनाव के कारण लंबे समय तक बीमार रहे और बिस्तर पर पड़ गए। इस दौरान, उनके उनकी मुलाकात जोधराजजी से तब हुई जब सूरत टेक्सटाइल मार्केट के व्यापारी करोड़ों रुपये की साड़ियों और ड्रेस मटेरियल का व्यापार कर रहे थे। वे लंबे समय से एक-दूसरे के साथ व्यापार कर रहे थे, इसलिए उनके बीच घनिष्ठ संबंध थे। जोधराजजी ने ऋकाभचंदजी को बताया कि अगर हम कडोदरा और जोल्वा में एक रंगाई-मुद्रण मिल परियोजना स्थापित करें, तो अच्छा मुनाफा होगा। और अगर हमारे अपने कपड़े छपेंगे और लोगों और व्यापारियों के कपड़े भी छपेंगे और रंगे जाएंगे, तो अच्छी आय होगी। इसलिए, जोधराजजी पर भरोसा करते हुए, उन्होंने मिल में लाखों रुपये का निवेश किया।

कुछ समय तक तो अच्छी आय हुई। फिर, जैसे-जैसे दिन बीतते गए, मिल में लाखों रुपये का घाटा होने लगा, जिसके कारण बैंगलोर के एक व्यापारी ऋकाभचंदजी को अचानक इसकी जानकारी मिली और उन्होंने सूरत में रहने वाले अपने रिश्तेदारों से बात की और उन्हीं रिश्तेदारों के माध्यम से ऋकाभचंदजी हमसे मिले। हमने उनकी मिल के आय-व्यय और घाटे पर चर्चा की। एक-दूसरे के बारे में सोचते हुए हम प्रतिभा मिल के मालिक प्रमोदभाई चौधरी जी की मिल गए और कडोदरा और जोल्वा मिल के घाटे के बारे में बात की। मिल पर बैंक का कर्ज था, मशीनरी पर कर्ज था और रंग व रसायन व्यापारियों का पैसा बकाया था, इसलिए मिल चलाना संभव नहीं था। एक-दूसरे के घाटे के कारण दोनों के रिश्ते खराब हो गए। फिर वे प्रतिभा मिल के मालिक प्रमोदभाई चौधरी जी से मिले। वे उनकी मिल गए और उनके दफ्तर में बैठकर एक-दूसरे के कर्ज और घाटे पर चर्चा की और मिल बेचने या बैंक का कर्ज चुकाने के लिए मिल और मशीनरी बेचने के बारे में बात की। एक-दूसरे की बातें सुनने के बाद वे मिल की मशीनरी और जमीन बेचकर एक-दूसरे से समझौता करने पर सहमत हो गए।

कर्नाटक के बेंगलुरु के चिकपेट में, प्रिंस एंटरप्राइज नाम की दुकान के मालिक जोराराम चौधरी थे। एक समय ऐसा था जब बेंगलुरु के चिकपेट स्थित प्रिंस नाम की दुकान चौबीसों घंटे, दिन-रात खुली रहती थी। एक समय कर्नाटक, दक्षिण प्रदेश और आंध्र प्रदेश में, बेंगलुरु के चिकपेट स्थित प्रिंस नाम की दुकान के मालिक बड़े-बड़े शोरूमों को लाखों-करोड़ों रुपये की साड़ियाँ और परिधान सामग्री की आपूर्ति करते थे। वे बेंगलुरु स्थित प्रिंस नाम की दुकान के मालिक जोराराम चौधरी और सूरत टेक्सटाइल मार्केट के व्यापारियों और मिल मालिकों को लाखों-करोड़ों रुपये की साड़ियाँ और परिधान सामग्री उधार देते थे। सूरत के व्यापारी आपसी भरोसे के आधार पर उन्हें साड़ियाँ और परिधान सामग्री उधार देते थे। लेकिन 6 दिसंबर को कोयंबटूर में शोभा नाम की एक दुकान के बहुत बड़े शोरूम में अचानक बम फटा और आग लग गई। शोभा नामक दुकान के शोरूम के मालिक को करोड़ों रुपये का भारी नुकसान हुआ। कोयंबटूर स्थित शोभा नामक इस दुकान को बेंगलुरु के प्रिंस नामक शोरूम से जोरा रामजी चौधरी के माध्यम से करोड़ों रुपये का माल मिलता था। आग लगने से हुए नुकसान के कारण उन्हें भारी हानि हुई। इससे उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और सूरत के कपड़ा व्यापारियों और मिल मालिकों को भुगतान करने में काफी कठिनाई हुई। एक मिल मालिक के माध्यम से जोरा रामजी चौधरी से संपर्क किया गया। उनके व्यवसाय की सारी जानकारी प्राप्त करने और नुकसान का कारण जानने के बाद, सूरत के व्यापारियों के माध्यम से उन्होंने पूनम एंटरप्राइजेज के नए नाम से प्रिंस नामक एक नई दुकान शुरू की। इसी प्रकार, विदेशों के कई शहरों जैसे इरोड, तिरुचि, बरगुर, कोयंबटूर, कृष्णागिरी, मद्रास और मुंबई के उल्हासनगर में व्यापारियों ने बिना किसी पुलिस कार्रवाई, झगड़े, असामाजिक तत्वों की किसी भी गड़बड़ी या अवैध कृत्य के अपने विवादों का निपटारा किया है।

हमारा संगठन बिना किसी कमीशन या किसी प्रकार की अपेक्षा के जनहित में काम कर रहा है। अन्य संगठनों और समूहों की तरह, जो तथाकथित सिंडिकेट समूहों के माध्यम से कार्यालय खोलकर बैठे रहते हैं, वे व्यापारियों, बिल्डरों और किसानों की जमीनों में फंसी रकम, साथ ही कई विलेख और लेनदेन के दस्तावेज भी वसूलते हैं। हीरे और कपड़ा बाजार के व्यापारियों से फंसी रकम की वसूली के लिए, ये सिंडिकेट फंसी हुई रकम का 30% से 35% हिस्सा वसूलते हैं और इसके अलावा विशिष्ट अग्रिम कार्यों के लिए भी पैसे लेते हैं। इस प्रकार, हमारा संगठन नीति और कानूनी न्याय प्रणाली के माध्यम से न्याय प्रदान करता है। और हमारा संगठन आज तक इसी उद्देश्य के साथ काम कर रहा है।

ईरान युद्ध का असर भारत के निवेश परिदृश्य पर: PE-VC निवेश में रिकॉर्ड गिरावट

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य की घटनाओं का असर अब सीधे भारत के निवेश बाजार में दिखने लगा है। मार्च 2026 के दौरान प्राइवेट इक्विटी (PE) और वेंचर कैपिटल (VC) निवेश में गंभीर गिरावट दर्ज की गई है। वेंचर इंटेलिजेंस की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, मार्च में कुल PE-VC निवेश मात्र 3.8 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल की समान अवधि में 4.7 अरब डॉलर था। इसका मतलब है कि निवेश में लगभग 19 प्रतिशत की कमी आई है। इसी तरह, 2026 की पहली तिमाही (जनवरी–मार्च) में कुल निवेश 9.10 अरब डॉलर रहा, जबकि 2025 की पहली तिमाही में यह 11.7 अरब डॉलर था, यानी 22 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली। विशेषज्ञों का कहना है कि इस गिरावट के पीछे वैश्विक अनिश्चितता, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव मुख्य कारण हैं। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने निवेशकों का भरोसा कमजोर कर दिया है। कई बड़े निवेशक जोखिम वाले सौदों से दूरी बना रहे हैं और पूंजी लगाने से पहले वैश्विक परिस्थितियों के स्थिर होने का इंतजार कर रहे हैं।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि बड़ी डील्स की संख्या में कमी आई है। इस साल पहली तिमाही में 10 करोड़ डॉलर या उससे अधिक मूल्य वाली डील्स की संख्या घटकर 17 रह गई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 29 ऐसी डील्स हुई थीं। इस गिरावट का असर कंपनियों के वैल्यूएशन पर भी पड़ा है। कई प्रमोटर अब उच्च मूल्यांकन पर पूंजी जुटाने से बच रहे हैं और केवल सामान्य होने पर ही बड़े सौदे करने की योजना बना रहे हैं।

तारकेश्वर नाथ वैष्णव के अनुसार, मौजूदा निवेश माहौल में भरोसा टूट रहा है और निवेशक केवल सुरक्षित विकल्पों पर ध्यान दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बनी रहेगी, निवेश गतिविधियों में तेजी आने की संभावना कम है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि मध्य पूर्व में संघर्ष बढ़ता है, तो भारत में निवेश पर और अधिक दबाव पड़ सकता है और कई स्टार्टअप और नवाचार परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाना कठिन हो जाएगा।

विश्लेषकों का मानना है कि निवेशक वर्तमान में जोखिम-रहित या कम जोखिम वाले क्षेत्रों में अपनी पूंजी लगाने को प्राथमिकता दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी और हेल्थकेयर जैसे सेक्टरों में निवेश अभी भी हो रहा है, लेकिन बड़े मर्जर और अधिग्रहण जैसी डील्स में कमी स्पष्ट है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अगर वैश्विक राजनीति में स्थिरता बनी रही और तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव नियंत्रित हुआ, तो 2026 की दूसरी तिमाही में निवेश गतिविधियों में सुधार देखने को मिल सकता है।

इस गिरावट से स्पष्ट है कि अंतरराष्ट्रीय तनाव और भू-राजनीतिक घटनाएं अब सीधे भारतीय निवेश परिदृश्य को प्रभावित कर रही हैं। निवेशकों का रुझान जोखिम से बचाव की ओर बढ़ रहा है, और यह संकेत देता है कि भारत में PE-VC बाजार को वैश्विक स्थिरता पर निर्भर रहना पड़ेगा। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि मध्य पूर्व और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच निवेशकों का विश्वास बहाल करने के लिए सरकारी नीतियों और प्रोत्साहन योजनाओं की आवश्यकता होगी, ताकि भारतीय स्टार्टअप और व्यवसायी जोखिम लेकर विकास कर सकें।

यह स्थिति साफ तौर पर यह दर्शाती है कि वैश्विक राजनीतिक घटनाओं का असर अब स्थानीय निवेश निर्णयों पर सीधे पड़ रहा है और निवेशक तेजी से बदलते भू-राजनीतिक माहौल को ध्यान में रखकर ही भविष्य की योजना बना रहे हैं।

सूरत चुनाव: युवा नेताओं को मौका देने का समय आ गया है, पुनरावृति न करने वाले फॉर्मूले की मांग करें

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सूरत नगर निगम चुनाव नजदीक आने के साथ ही भाजपा समेत अन्य राजनीतिक दलों के कार्यालयों में भी चहल-पहल शुरू हो गई है। भाजपा कार्यालय में तो मानो तूफान सा आ गया है, क्योंकि प्रत्येक वार्ड में आधा दर्जन उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। वहीं दूसरी ओर, अन्य दल उम्मीदवार जुटाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

इसलिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर हम सामान्य तौर पर बात करें तो एक बात निश्चित है कि जो पार्टी लंबे समय से सत्ता में है, उसे दो-तीन बार चुने गए चेहरों को दरकिनार कर नए चेहरों को मौका देना चाहिए। यह समय की मांग है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग बार-बार चुने जाते हैं लेकिन रिश्वतखोरी, जबरन वसूली, छेड़छाड़, बलात्कार या किसी अन्य अपराध में

लिप्त हैं, उन्हें दोबारा टिकट नहीं दिया जाना चाहिए, चाहे वे इसमें शामिल हों या न हों। यानी, पार्टी ने 'दोबारा चुनाव न कराने' का फॉर्मूला अपनाया है, जिसमें अनुभवी युवाओं को प्राथमिकता दी गई है, जिन्होंने 20-30 वर्षों तक जमीनी स्तर पर पार्टी के लिए सक्रिय रूप से काम किया है और पार्टी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया है, साथ ही उन युवा चेहरों को भी जो दस वर्षों से अधिक समय से पार्टी के साथ हैं और अपना समय पार्टी के लिए समर्पित किया है, और उन नए चेहरों को भी जिनमें देश सेवा की प्रबल भावना है। पार्टी ने युवा नेताओं को नेतृत्व सौंपकर उन्हें टिकट आवंटित किए हैं ताकि वे शहर और देश दोनों के लिए योगदान दे सकें। यही समय की मांग है।

एचडीएफसी बैंक की मजबूत रफ्तार: चौथी तिमाही में ऋण और जमा दोनों में दोहरी बढ़त, लोन बुक 29.6 लाख करोड़ के पार

नई दिल्ली। देश के निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंकों में शामिल HDFC Bank ने वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही (जनवरी–मार्च) के लिए जारी अपने प्रारंभिक व्यावसायिक अपडेट में शानदार प्रदर्शन दर्ज किया है। बैंक के कुल अग्रिम यानी लोन बुक में सालाना आधार पर 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जिससे यह आंकड़ा 31 मार्च 2026 तक बढ़कर 29.60 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। एक साल पहले इसी अवधि में यह 26.43 लाख करोड़ रुपये था, जो इस बात का संकेत है कि बैंक की क्रेडिट ग्रोथ लगातार मजबूत बनी हुई है।

बैंक के इस प्रदर्शन को भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ती क्रेडिट मांग और उपभोक्ता व कॉरपोरेट सेक्टर में ऋण की जरूरतों में तेजी से जोड़कर देखा जा रहा है। खास तौर पर रिटेल लोन, होम लोन और एमएसएमई सेक्टर में ऋण की मांग बढ़ने से बैंक की लोन बुक में यह उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि एचडीएफसी बैंक ने अपने मजबूत जोखिम प्रबंधन और विविध ऋण पोर्टफोलियो के कारण इस चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल में भी संतुलित वृद्धि बनाए रखी है।

केवल ऋण ही नहीं, बल्कि जमा (डिपॉजिट) के मोर्चे पर भी बैंक ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। कुल जमा में 14.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे यह बढ़कर 31.05 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 27.14 लाख करोड़ रुपये था। यह वृद्धि दर्शाती है कि ग्राहकों का बैंक पर भरोसा मजबूत बना हुआ है और बैंक अपनी जमा आधार को लगातार विस्तार दे रहा है।

जमा संरचना के भीतर भी संतुलित वृद्धि देखने को मिली है। चालू और बचत खाते यानी CASA डिपॉजिट में 12.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो अब 10.6 लाख करोड़ रुपये हो गया है। एक वर्ष पहले यह आंकड़ा 9.4 लाख करोड़ रुपये था। CASA डिपॉजिट को बैंकिंग सेक्टर में सस्ती फंडिंग का प्रमुख स्रोत माना जाता है, और इसमें वृद्धि से बैंक की लागत नियंत्रण क्षमता मजबूत होती है। इसके साथ ही, समयबद्ध जमा यानी टर्म डिपॉजिट में भी 15.5 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो 20.45 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 17.7 लाख करोड़ रुपये था। टर्म डिपॉजिट में यह तेजी इस बात का संकेत है कि उच्च ब्याज दरों के माहौल में ग्राहक लंबी अवधि के निवेश को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे बैंक को स्थिर फंडिंग प्राप्त हो रही है।

विश्लेषकों का मानना है कि एचडीएफसी बैंक का यह प्रदर्शन ऐसे समय में आया है जब वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता बनी हुई है और निवेश व वित्तीय गतिविधियों पर दबाव देखा जा रहा है। इसके बावजूद बैंक ने अपने मूलभूत व्यवसाय—ऋण वितरण और जमा संग्रह—दोनों में संतुलित वृद्धि बनाए रखी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बैंक की रणनीति दीर्घकालिक और स्थिर विकास पर केंद्रित है।

बैंक द्वारा जारी ये आंकड़े प्रारंभिक व्यावसायिक अपडेट हैं और इसमें अंतिम वित्तीय परिणाम शामिल नहीं हैं। HDFC Bank 18 अप्रैल 2026 को अपनी चौथी तिमाही के विस्तृत वित्तीय परिणाम जारी करेगा, जिसमें लाभ, एनपीए स्तर, मार्जिन और अन्य वित्तीय संकेतकों का विस्तृत विश्लेषण सामने आएगा। बाजार और निवेशकों की नजर अब इन विस्तृत परिणामों पर टिकी हुई है, ताकि बैंक के समग्र प्रदर्शन का आकलन किया जा सके। बैंकिंग विशेषज्ञों का कहना है कि एचडीएफसी बैंक की यह वृद्धि भारतीय बैंकिंग सेक्टर की मजबूती को भी दर्शाती है। खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक बाजार अस्थिर हैं और निवेश में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है, इस तरह की स्थिर वृद्धि घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है।

कुल मिलाकर, एचडीएफसी बैंक का यह प्रदर्शन यह दर्शाता है कि बैंक ने अपनी मजबूत ग्राहक आधार, तकनीकी दक्षता और जोखिम प्रबंधन के जरिए बाजार में अपनी पकड़ बनाए रखी है।

गुजरात में समान नागरिक संहिता कानून पर विवाद: मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हाईकोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया

गुजरात। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने गुजरात विधानसभा द्वारा हाल ही में पारित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक को संविधान के मूल सिद्धांतों और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ करार देते हुए इसकी उच्च न्यायालय में चुनौती देने का ऐलान किया है। बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास और अन्य पदाधिकारी इसे मुस्लिम समुदाय के सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर प्रत्यक्ष हमला मानते हैं और उनका कहना है कि यह विधेयक न केवल अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों का उल्लंघन करता है बल्कि बहुसंख्यकवादी सामाजिक मान्यताओं को थोपने का प्रयास भी है।

बोर्ड ने स्पष्ट किया कि इस विधेयक में बलपूर्वक, दबाव या धोखाधड़ी से किए गए विवाह के लिए सात वर्ष की कारावास की सजा का प्रावधान है, जबकि बहुविवाह पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा विवाह और लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य किया गया है। बोर्ड का तर्क है कि उत्तराखंड में लागू इसी प्रकार का कानून भी संवैधानिक रूप से विवादास्पद और कानूनी रूप से अस्थिर साबित हुआ है। इलियास ने कहा कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत नीति निर्देशक तत्व के रूप

में वर्णित समान नागरिक संहिता के सिद्धांत से भटकता है, क्योंकि अनुच्छेद 44 केवल एक मार्गदर्शक नीति है और इसे मौलिक अधिकारों की तरह सीधे लागू नहीं किया जा सकता।

बोर्ड ने यह भी कहा कि गुजरात का यह प्रस्तावित कानून न तो पूरे देश में लागू होता है और न ही राज्य के भीतर समान रूप से, क्योंकि अनुसूचित जनजातियों और अन्य संवैधानिक रूप से संरक्षित समुदायों को इस कानून से छूट दी गई है। इस कारण इसे वास्तविक समान नागरिक संहिता नहीं कहा जा सकता और केवल इसका नाम ही भ्रामक है। बोर्ड का मानना है कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया था कि जनता की सहमति के बिना किसी भी नागरिक पर कानून थोपना उचित नहीं होगा। उन्होंने याद दिलाया कि 21वें और 22वें विधि आयोगों ने इस मुद्दे पर जनता की राय ली थी और निष्कर्ष निकाला था कि वर्तमान परिस्थितियों में समान नागरिक संहिता लागू करना आवश्यक नहीं है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल है। इसके तहत विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और पारिवारिक कानूनों में इस्लामी धर्मशास्त्र और धार्मिक परंपराओं का पालन करने का अधिकार समुदाय को प्राप्त है। बोर्ड ने आरोप लगाया कि गुजरात का यह प्रस्तावित कानून इस संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है और अल्पसंख्यक समुदायों पर बहुसंख्यकवादी सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को थोपने का प्रयास है।

बोर्ड के प्रवक्ता ने कहा कि इस विधेयक को तत्काल प्रभाव से लागू नहीं किया जाना चाहिए और इसकी कानूनी समीक्षा के बिना किसी भी तरह के कार्यान्वयन से रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि भविष्य में पारिवारिक कानूनों में किसी भी सुधार या बदलाव को केवल संविधान की गारंटी और उचित कानूनी ढांचे के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए, जिसमें सभी हितधारकों, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदायों, के साथ व्यापक परामर्श शामिल हो।

इस विवादित विधेयक के पारित होते ही राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह स्पष्ट किया है कि वे न्यायालय के माध्यम से संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे और कानून के प्रभावों को रोकने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। बोर्ड ने इस अवसर पर यह भी कहा कि इस तरह के कानूनों का चुनावी समय में प्रस्तावित होना सवाल खड़ा करता है और इसे केवल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए पेश किया गया माना जा सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि गुजरात का यह विधेयक पूरे देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के बहाने अल्पसंख्यकों के अधिकारों में कटौती का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इसे लेकर कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लंबी खींच सकती है और उच्च न्यायालय में इस विधेयक की वैधता पर निर्णायक फैसला आने तक विवाद जारी रह सकता है।

असारवा - कानपुर सेंट्रल साप्ताहिक विशेष ट्रेन का संचालन

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा एवं मांग को ध्यान में रखते हुए असारवा एवं कानपुर सेंट्रल के बीच साप्ताहिक विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

v ट्रेन संख्या 01906/01905
असारवा – कानपुर सेंट्रल
साप्ताहिक विशेष ट्रेन

ट्रेन संख्या 01906 असारवा – कानपुर सेंट्रल विशेष ट्रेन दिनांक 07 अप्रैल 2026 से 14 जुलाई 2026 तक प्रत्येक मंगलवार को असारवा से 08:55 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन बुधवार को 07:00 बजे कानपुर सेंट्रल पहुँचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 01905 कानपुर सेंट्रल – असारवा विशेष ट्रेन दिनांक 06 अप्रैल 2026 से 13 जुलाई 2026 तक प्रत्येक सोमवार को कानपुर सेंट्रल से 08:15 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन मंगलवार को 05:45 बजे असारवा पहुँचेगी।

मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन हिम्मतनगर, शामलाजी रोड, डूंगरपुर, सेमारी, जावर, उदयपुर सिटी, राणा प्रतापनगर, मावली जंक्शन, चंदेरिया, मांडलगढ़, बूंदी, केशोराय पाटन, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, बयाना जंक्शन, रूपबास, फतेहपुर सीकरी, इदगाह, टुंडला जंक्शन, फिरोजाबाद और इटावा स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में 2 टियर एसी, 3 टियर एसी, स्लीपर एवं सामान्य श्रेणी के कोच रहेंगे। ट्रेन संख्या 01906 असारवा – कानपुर सेंट्रल के लिए आरक्षण 05 अप्रैल 2026 से सभी PRS काउंटरों तथा IRCTC वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

ट्रेनों के ठहराव, समय एवं संरचना संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर अवलोकन कर सकते हैं।

मेगा ट्रैफिक ब्लॉक के कारण अहमदाबाद मंडल की दो ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन

उत्तर रेलवे के अंतर्गत कानपुर–लखनऊ खंड में ब्रिज संख्या 110 पर स्टील ट्रफ हटाने एवं H-बीम स्लीपर लगाने हेतु दिनांक 02 अप्रैल, 2026 से 13 मई, 2026 तक मेगा ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक लिया गया है। इस कार्य के कारण पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल से संचालित निम्नलिखित ट्रेनों के मार्ग में अस्थायी परिवर्तन किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संख्या 09465 अहमदाबाद – दरभंगा क्लोन स्पेशल दिनांक 03, 10, 17 और 24 अप्रैल तथा 01 और 08 मई 2026 को अपने निर्धारित मार्ग वाया कानपुर सेंट्रल – लखनऊ – बाराबंकी – शाहगंज – छपरा – मुजफ्फरपुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया कानपुर सेंट्रल – प्रयागराज – पं. दीन दयाल उपाध्याय – पाटलिपुत्र – मुजफ्फरपुर होकर चलेगी एवं लखनऊ, अयोध्या कैंट, शाहगंज और छपरा स्टेशनो पर नहीं जाएगी।

ट्रेन संख्या 15270 साबरमती – मुजफ्फरपुर जनसाधारण एक्सप्रेस दिनांक 04, 11, 18 और 25 अप्रैल तथा 02 और 09 मई 2026 को अपने निर्धारित मार्ग वाया कानपुर सेंट्रल – लखनऊ – बाराबंकी – गोरखपुर – छपरा – सोनपुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया कानपुर सेंट्रल – प्रयागराज – मिर्ज़ापुर – पं. दीन दयाल उपाध्याय – पाटलिपुत्र – सोनपुर होकर चलेगी एवं लखनऊ, गोंडा, बस्ती, खलीदाबाद, गोरखपुर, देवरिया सदर, भटनी, सीवान और छपरा स्टेशनो पर नहीं जाएगी।

ट्रेनों के ठहराव, समय एवं संरचना संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर अवलोकन कर सकते हैं।

ईरानी तेल को लेकर भ्रम पर सरकार का सख्त जवाब: चीन की ओर मुड़े टैंकर का दावा निराधार, सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित

नई दिल्ली। ईरान से कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर फैली अटकलों और सोशल मीडिया पर चल रही खबरों पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट और सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि भारत की ऊर्जा आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित है और भुगतान में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने साफ किया कि भारतीय रिफाइनरियां सामान्य रूप से कच्चे तेल की खरीद कर रही हैं और किसी भी टैंकर के चीन की ओर मुड़ने का दावा पूरी तरह भ्रामक और तथ्यों से परे है।

मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जारी अपने बयान में उन रिपोर्ट्स को खारिज किया, जिनमें कहा गया था कि ईरान से कच्चा तेल लेकर आ रहा एक टैंकर भारत पहुंचने के बजाय चीन की ओर मुड़ गया। सरकार के अनुसार, तेल परिवहन उद्योग में यह एक सामान्य प्रक्रिया है कि जहाज परिचालन आवश्यकताओं, लॉजिस्टिक्स और व्यावसायिक कारणों के चलते अपने मार्ग या गंतव्य में बदलाव कर सकते हैं। ऐसे में किसी एक जहाज की दिशा बदलने को भुगतान या कूटनीतिक समस्या से जोड़ना पूरी तरह गलत है।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि उक्त खेप भारत आती, तो यह लगभग सात वर्षों में ईरान से आने वाली पहली कच्चे तेल की खेप होती। इस संदर्भ में यह दावा कि भुगतान में किसी बाधा के कारण जहाज ने अपना मार्ग बदला, पूरी तरह निराधार है। मंत्रालय का कहना है कि भारत और ईरान के बीच ऊर्जा व्यापार को लेकर किसी भी स्तर पर भुगतान संकट की स्थिति नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए 40 से अधिक देशों से कच्चे तेल का आयात करता है। भारतीय तेल कंपनियों को वैश्विक बाजार से तेल खरीदने में पूर्ण व्यावसायिक स्वतंत्रता प्राप्त है, जिससे वे विभिन्न स्रोतों से कच्चा तेल खरीदकर आपूर्ति को संतुलित बनाए रखती हैं। पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद भारत ने अपनी ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को स्थिर बनाए रखा है।

सरकार ने यह भी जानकारी दी कि ईरान से लगभग 44 हजार टन एलपीजी लेकर आया एक जहाज 2 अप्रैल को मंगलौर बंदरगाह पहुंच चुका है और वहां माल उतारने की प्रक्रिया जारी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत और ईरान के बीच ऊर्जा व्यापार पूरी तरह बंद नहीं हुआ है और आवश्यक आपूर्ति नियमित रूप से जारी है। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर तेल आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता और मध्य पूर्व में जारी तनाव के कारण इस प्रकार की अफवाहें तेजी से फैलती हैं। हालांकि भारत ने अपनी ऊर्जा नीति में विविधता और लचीलापन बनाए रखा है, जिससे किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम होती है और संकट की स्थिति में भी आपूर्ति प्रभावित नहीं होती।

सरकार ने आम जनता और उद्योग जगत से अपील की है कि वे इस प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें। मंत्रालय का कहना है कि आने वाले महीनों के लिए भारत की कच्चे तेल और एलपीजी की जरूरतें पूरी तरह सुरक्षित हैं और आपूर्ति को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच सरकार का यह स्पष्टीकरण ऊर्जा बाजार में स्थिरता और भरोसा बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

गांधीनगर में नशे के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार: एएनटीएफ की कार्रवाई से बेनकाब होती तस्करी की गहरी जड़ें

गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) द्वारा की गई हालिया कार्रवाई ने न केवल नशीले पदार्थों की तस्करी के एक सक्रिय चैनल को उजागर किया है, बल्कि यह भी संकेत दिया है कि राज्य में ड्रग नेटवर्क कितनी गहराई तक फैला हुआ है और किस प्रकार संगठित तरीके से काम कर रहा है। मोटा चिलोडा इलाके में की गई इस कार्रवाई में करीब 12 किलोग्राम गांजा के साथ दो तस्करों की गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और खुफिया तंत्र की मजबूती को भी सामने रखा है।

यह पूरा ऑपरेशन एक नियमित गश्त के दौरान मिली गुप्त सूचना के आधार पर अंजाम दिया गया। एएनटीएफ की गांधीनगर जोन की टीम ने चिलोडा सर्कल के पास एक सरकारी बस को रोका, जो सामान्य तौर पर एक साधारण यात्री वाहन प्रतीत हो रही थी, लेकिन खुफिया इनपुट के आधार पर उसमें तस्करी की आशंका जताई गई थी। जब टीम ने संदिग्धों की जांच की, तो उनके पास से 11.94 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 5.97 लाख रुपए आंकी गई। इसके साथ ही दो मोबाइल फोन भी जब्त किए गए, जिनकी कीमत करीब 10 हजार रुपए बताई गई है। इस प्रकार कुल जब्त सामग्री की कीमत 6.07 लाख रुपए तक पहुंच गई।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान विराज सोलंकी (26) और आदित्य उर्फ आदि बराइया (22) के रूप में हुई है। दोनों युवक अलग-अलग इलाकों के रहने वाले हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह नेटवर्क केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न स्थानों के लोगों को जोड़कर संचालित किया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि ये आरोपी केवल छोटे स्तर के कैरियर नहीं, बल्कि एक बड़े सप्लाई चेन का हिस्सा हो सकते हैं, जो राज्य के भीतर और संभवतः बाहर तक फैला हुआ है।

इस पूरे अभियान का नेतृत्व इंस्पेक्टर एनआर पटेल ने किया, जिनके साथ केएम वडनगारा, पीएस जाला, पीएम चावड़ा सहित अन्य पुलिसकर्मी और एक तकनीकी विशेषज्ञ भी शामिल थे। टीम ने जिस सटीकता और तत्परता से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, वह इस बात का प्रमाण है कि एएनटीएफ अब केवल पारंपरिक तरीकों से ही नहीं, बल्कि तकनीकी और खुफिया जानकारी के संयोजन से भी काम कर रही है।

इस मामले में आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है, जिनमें धारा 8(सी), 20(बी)(2)(बी) और 29 शामिल हैं। ये धाराएं न केवल नशीले पदार्थों के कब्जे और तस्करी को अपराध मानती हैं, बल्कि आपराधिक साजिश और नेटवर्क के संचालन को भी कड़ी सजा के दायरे में लाती हैं। इसके तहत दोषी पाए जाने पर आरोपियों को लंबी अवधि की सजा और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

इस घटना को यदि व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि गुजरात में हाल के महीनों में नशीले पदार्थों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। फरवरी में भावनगर जिले में अधिकारियों ने एक बड़ी अवैध खेती का भंडाफोड़ किया था, जिसमें गांजा और अफीम जैसी फसलों की खेती की जा रही थी। इस कार्रवाई में 10.9 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के नशीले पदार्थ जब्त किए गए थे, जो राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी जब्तियों में से एक मानी जाती है।

इसी प्रकार मार्च महीने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने एक शहरी नेटवर्क का पर्दाफाश किया था, जहां एक किराए के अपार्टमेंट से 26 लाख रुपए से अधिक कीमत का हाइब्रिड गांजा बरामद किया गया था। यह मामला इस बात का उदाहरण है कि ड्रग तस्कर अब पारंपरिक तरीकों के बजाय शहरी क्षेत्रों में छिपकर आधुनिक तरीकों से अपना नेटवर्क चला रहे हैं।

हाल ही में साबरकांठा जिले के प्रांतिज इलाके में भी एएनटीएफ ने 5.177 किलोग्राम गांजा जब्त किया था और एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। इस मामले में भी जांच के दौरान यह सामने आया कि तस्करी का यह नेटवर्क कई जिलों और राज्यों तक फैला हुआ हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि नशीले पदार्थों की तस्करी अब केवल सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि यह देश के आंतरिक हिस्सों में भी तेजी से फैल रही है। युवा वर्ग को निशाना बनाकर इस नेटवर्क को विस्तार दिया जा रहा है, जिससे समाज में गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। गुजरात सरकार और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई इस दिशा में एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन यह भी जरूरी है कि समाज के स्तर पर जागरूकता बढ़ाई जाए और युवाओं को इस खतरे से दूर रखा जाए। स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संस्थाओं को भी इस अभियान में शामिल करना आवश्यक है, ताकि नशे के खिलाफ एक व्यापक जन आंदोलन खड़ा किया जा सके।

गांधीनगर में हुई यह कार्रवाई केवल एक सफलता नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है कि ड्रग तस्करी के खिलाफ लड़ाई अभी लंबी है। एएनटीएफ और अन्य एजेंसियों को लगातार सतर्क रहकर इस नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचना होगा, ताकि न केवल तस्करों को पकड़ा जा सके, बल्कि इस अवैध कारोबार को पूरी तरह खत्म किया जा सके।

इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां अब पहले से अधिक सक्रिय और सक्षम हो चुकी हैं। यदि इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहती है, तो आने वाले समय में नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में निश्चित रूप से बड़े परिणाम देखने को मिल सकते हैं।

गंभीरा ब्रिज के पुनः खुलने से लौटी रफ्तार: वडोदरा–आनंद के बीच आवागमन में आया नया जीवन, सुरक्षा के साथ बढ़ा भरोसा

वडोदरा। गुजरात के वडोदरा और आनंद जिले के बीच आवागमन को नई गति देने वाला गंभीरा ब्रिज एक बार फिर से लोगों के लिए जीवनरेखा बनकर उभरा है। पादरा के मुजपुर को अंकलाव से जोड़ने वाला यह महत्वपूर्ण पुल जब से दोबारा शुरू हुआ है, तब से क्षेत्र में ट्रैफिक का दबाव तेजी से बढ़ा है और लोगों को आवागमन में पहले की तुलना में काफी राहत मिली है। लंबे समय तक बाधित रहने के बाद जैसे ही यह पुल दोबारा चालू हुआ, वैसे ही हजारों की संख्या में लोग इसका उपयोग करने लगे, जिससे इसकी उपयोगिता और महत्व स्पष्ट रूप से सामने आया है।

रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट द्वारा किए गए हालिया ट्रैफिक सेंसस ने इस बदलाव को आंकड़ों के माध्यम से भी प्रमाणित किया है। महज 24 घंटे के भीतर इस ब्रिज से 14,551 टू-व्हीलर का आवागमन दर्ज किया गया, जो यह दर्शाता है कि यह पुल स्थानीय लोगों के लिए कितनी बड़ी जरूरत है। इनमें से 7,252 बाइक वडोदरा से आनंद की ओर गईं, जबकि 7,299 बाइक आनंद से वडोदरा की दिशा में आईं। यह लगभग संतुलित आंकड़ा इस बात का संकेत देता है कि दोनों शहरों के बीच आवागमन समान रूप से सक्रिय है और यह पुल दोनों ओर के लोगों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है।

यदि समय के हिसाब से देखा जाए तो सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक का समय सबसे अधिक व्यस्त पाया गया है। यह वही समय है जब लोग अपने काम, व्यवसाय या शिक्षा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं। ऐसे में इस पुल का चालू होना न केवल समय की बचत कर रहा है, बल्कि लोगों के दैनिक जीवन को भी अधिक सुगम बना रहा है।

केवल वाहन चालकों के लिए ही नहीं, बल्कि पैदल यात्रियों के लिए भी यह पुल एक महत्वपूर्ण मार्ग बन गया है। आंकड़ों के अनुसार, इसी 24 घंटे की अवधि में 1,182 लोग वडोदरा से आनंद की ओर और 1,305 लोग आनंद से वडोदरा की ओर पैदल चलते हुए इस पुल को पार करते नजर आए। पैदल यात्रियों के लिए सुबह 9 बजे से 11 बजे तक का समय सबसे अधिक व्यस्त रहा, जो यह दर्शाता है कि स्थानीय स्तर पर छोटे-छोटे कामों के लिए भी लोग इस पुल पर निर्भर हैं।

गौरतलब है कि कुछ समय पहले इस पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके कारण इसे बंद करना पड़ा था। इस घटना ने न केवल आवागमन को प्रभावित किया, बल्कि लोगों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता पैदा कर दी थी। हालांकि, रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए इस समस्या का समाधान निकाला। टूटे हुए हिस्से को लोहे के मजबूत स्ट्रक्चर के माध्यम से जोड़कर इसे फिर से उपयोग के योग्य बनाया गया, जिससे यह पुल एक बार फिर से चालू हो सका। इस मरम्मत कार्य में विश्वकर्मा इंजीनियरिंग का सहयोग लिया गया, जिसने तकनीकी रूप से इस पुल को सुरक्षित और स्थिर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अधिकारियों के अनुसार, पुल को दोबारा शुरू करने से पहले सभी आवश्यक तकनीकी परीक्षण किए गए, जिनमें लोड टेस्टिंग भी शामिल थी। यह सुनिश्चित किया गया कि पुल पर सीमित भार के साथ सुरक्षित आवागमन संभव हो सके। डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अक्षय जोशी ने बताया कि सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पुल के दोनों सिरों पर बैरिकेडिंग की गई है, ताकि अनियंत्रित प्रवेश को रोका जा सके। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। पुल पर पुलिस, होमगार्ड और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की गई है, ताकि यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखा जा सके।

इसके अलावा, पुल पर क्रैश बैरियर लगाए गए हैं, जो किसी भी दुर्घटना की स्थिति में वाहन को नियंत्रित रखने में मदद करेंगे। रोड सेफ्टी साइनबोर्ड के माध्यम से वाहन चालकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं, जबकि लेन को व्यवस्थित रखने के लिए स्प्रिंग पोस्ट लगाए गए हैं। इन सभी उपायों का उद्देश्य केवल एक ही है—लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी प्रकार की दुर्घटना की संभावना को न्यूनतम करना।

प्रशासन ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि इस पुल पर केवल टू-व्हीलर और पैदल यात्रियों को ही आवागमन की अनुमति है। भारी वाहनों को फिलहाल इस मार्ग से दूर रखा गया है, ताकि पुल पर अतिरिक्त दबाव न पड़े और इसकी संरचना सुरक्षित बनी रहे। यह निर्णय पूरी तरह से तकनीकी और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित स्पीड लिमिट का पालन करें और ट्रैफिक नियमों का सख्ती से अनुसरण करें। पुल पर लापरवाही या तेज गति से वाहन चलाना न केवल स्वयं के लिए, बल्कि अन्य लोगों के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है।

गंभीरा ब्रिज का पुनः संचालन केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली नहीं है, बल्कि यह स्थानीय लोगों के जीवन में सामान्यता और गति की वापसी का प्रतीक है। यह पुल न केवल दो स्थानों को जोड़ता है, बल्कि लोगों के रोजमर्रा के जीवन, उनके कामकाज और सामाजिक गतिविधियों को भी सुचारु रूप से चलाने में मदद करता है। आने वाले समय में यदि इसी प्रकार की सतर्कता और रखरखाव जारी रहा, तो यह पुल लंबे समय तक लोगों की सेवा करता रहेगा। फिलहाल, इसके पुनः खुलने से जो राहत और सुविधा लोगों को मिली है, वह इस बात का प्रमाण है कि सही समय पर उठाए गए कदम किस प्रकार बड़े स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।

सूरत में नारी सशक्तिकरण की नई मिसाल: मारवाड़ी युवा मंच की पहल से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम

सूरत। गुजरात के प्रमुख औद्योगिक शहर सूरत में सामाजिक जागरूकता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल सामने आई है, जहां मारवाड़ी युवा मंच सूरत जागृति शाखा ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एक नई योजना की शुरुआत की है। यह पहल केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने और उन्हें समाज में एक सशक्त पहचान दिलाने की दिशा में एक ठोस कदम के रूप में देखी जा रही है।

इस योजना के अंतर्गत शाखा द्वारा एक पुलिस स्टेशन में महिलाओं के उत्थान के लिए 21,000 की सहयोग राशि प्रदान की गई है, जिससे एक छोटी दुकान की शुरुआत की जा सके। यह दुकान केवल एक व्यवसायिक गतिविधि नहीं, बल्कि उन महिलाओं के लिए एक अवसर है जो अब तक आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर थीं। इस दुकान के माध्यम से वे न केवल अपनी आय अर्जित कर सकेंगी, बल्कि अपने जीवन में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी हासिल करेंगी।

इस पहल की खास बात यह है कि इसे केवल एक बार की सहायता के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे एक सतत और दीर्घकालिक योजना के रूप में विकसित किया गया है। इसी सोच के तहत मारवाड़ी युवा मंच ने गृह उद्योग योजना की भी शुरुआत की है, जिसके माध्यम से महिलाएं अपने घर पर रहकर विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार कर सकेंगी। इन उत्पादों में

आर्टिफिशियल ज्वेलरी, रेज़िन आर्ट, तोरण, आरती की थाली और कपड़े के थैले शामिल हैं। ये सभी उत्पाद न केवल पारंपरिक कला और कौशल को बढ़ावा देते हैं, बल्कि बाजार में भी इनकी अच्छी मांग है।

इस योजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इन उत्पादों की बिक्री महिला पुलिस की निगरानी में की जाएगी, जिससे पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इससे महिलाओं को बाजार तक पहुंच बनाने में भी मदद मिलेगी, जो अक्सर उनके लिए एक बड़ी चुनौती होती है। इस व्यवस्था के तहत होने वाली पूरी आमदनी सीधे उन महिलाओं को दी जाएगी, जो इन उत्पादों का निर्माण करेंगी। इस प्रकार यह योजना महिलाओं को न केवल रोजगार प्रदान करती है, बल्कि उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में भी अग्रसर करती है।

सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो यह पहल कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है। एक ओर जहां यह महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है, वहीं दूसरी ओर यह समाज में उनके प्रति दृष्टिकोण को भी बदलने का काम करती है। जब महिलाएं आत्मनिर्भर बनती हैं, तो वे अपने परिवार और समाज में अधिक सम्मान प्राप्त करती हैं। इससे उनके निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है और वे अपने जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले स्वयं लेने में सक्षम हो जाती हैं।

इस पूरे प्रोजेक्ट को सफल बनाने में शाखा की अध्यक्ष सुनीता खेतान का नेतृत्व विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है। उनके साथ संस्थापक प्रेरणा भाऊवाला तथा सदस्य सपना खेराड़ी, गरिमा जैन और सुनीता सरावगी ने भी सक्रिय भूमिका निभाई है। इन सभी महिलाओं ने मिलकर यह साबित किया है कि यदि सही दिशा में प्रयास किए जाएं, तो समाज में सकारात्मक बदलाव लाना संभव है।

मारवाड़ी युवा मंच द्वारा उठाया गया यह कदम केवल एक संगठन की पहल नहीं, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। यह उन सभी संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए एक प्रेरणा है, जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं लेकिन सही दिशा और अवसर की तलाश में हैं।

इस पहल के माध्यम से यह संदेश भी दिया गया है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केवल बड़े-बड़े सरकारी कार्यक्रमों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि छोटे-छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। यदि समाज के विभिन्न वर्ग मिलकर इस दिशा में काम करें, तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकता है।

संस्था ने इस परियोजना में सहयोग देने वाले सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है और यह भी आश्वासन दिया है कि भविष्य में भी ऐसे सामाजिक कार्य निरंतर जारी रखे जाएंगे। यह प्रतिबद्धता इस बात का संकेत है कि यह पहल केवल एक शुरुआत है और आने वाले समय में इसे और अधिक विस्तार दिया जाएगा।

आज के समय में जब महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ रही है, ऐसे में इस प्रकार की पहलें उन्हें और अधिक अवसर प्रदान करती हैं। सूरत में शुरू की गई यह योजना न केवल स्थानीय स्तर पर प्रभाव डालेगी, बल्कि अन्य शहरों और राज्यों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी। यदि इसी प्रकार की योजनाएं देशभर में लागू की जाएं, तो निश्चित रूप से भारत में नारी सशक्तिकरण को एक नई दिशा और गति मिल सकती है।

जब सहारा भी कम पड़ जाए: डीग अस्पताल का वायरल वीडियो और व्यवस्था पर उठते सवाल

राजस्थान के डीग जिला अस्पताल से सामने आया एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों के दिलों को झकझोर रहा है। यह कोई साधारण दृश्य नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो हमारे स्वास्थ्य तंत्र की कमियों और आम आदमी की मजबूरी को एक साथ उजागर करती है। अस्पताल, जहां बीमार और जरूरतमंद लोगों को सहारा और सुविधा मिलनी चाहिए, वहीं एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी बीमार पत्नी को साइकिल पर बैठाकर इमरजेंसी वार्ड से बाहर ले जाता दिखाई देता है। यह दृश्य जितना भावुक है, उतना ही असहज करने वाला भी, क्योंकि यह केवल एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है।

इस बुजुर्ग की कहानी केवल एक वीडियो तक सीमित नहीं है। बताया गया है कि वह अपनी पत्नी को हर 4 से 5 दिन में इलाज के लिए इसी अस्पताल लेकर आता है। उसके पास न एंबुलेंस की सुविधा है, न ही स्ट्रेचर या व्हीलचेयर जैसी मूलभूत सहायता। उसकी सबसे बड़ी ताकत और साधन है उसकी पुरानी साइकिल, जिस पर वह अपनी पत्नी को बैठाकर अस्पताल तक लाता है और इलाज के बाद उसी तरह वापस ले जाता है। यह दृश्य उस जिम्मेदारी, प्रेम और समर्पण को दर्शाता है, जो उम्र के इस अंतिम पड़ाव पर भी कम नहीं हुआ है।

एक ओर यह घटना पति-पत्नी के रिश्ते की गहराई और सच्चे प्रेम का उदाहरण पेश करती है, वहीं दूसरी ओर यह हमारे स्वास्थ्य तंत्र की वास्तविक स्थिति को भी उजागर करती है। सवाल यह उठता है कि क्या एक सरकारी अस्पताल में इतनी भी सुविधा नहीं होनी चाहिए कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को अपनी बीमार पत्नी को साइकिल पर लाने की नौबत आए? क्या स्ट्रेचर, व्हीलचेयर या अस्पताल के भीतर

परिवहन की व्यवस्था इतनी दुर्लभ हो गई है कि लोग खुद ही अपने समाधान ढूंढने को मजबूर हैं?

अस्पताल प्रशासन ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन वह भी कई सवालों को जन्म देती है। अस्पताल के पीएमओ जितेंद्र फौजदार ने स्वीकार किया कि यह वीडियो डीग अस्पताल का ही है और यह बुजुर्ग नियमित रूप से अपनी पत्नी को दिखाने आता है। वहीं, सीएमएचओ ने कहा कि उनके पास इस बुजुर्ग की पूरी जानकारी नहीं है और यदि वह दोबारा आता है, तभी उसके बारे में विस्तार से पता चल सकेगा।

प्रशासन का यह भी कहना है कि अस्पताल परिसर में साइकिल या बाइक को रोक पाना आसान नहीं है। उनका तर्क है कि यदि लोगों को बाहर वाहन खड़ा करने को कहा जाए, तो चोरी का खतरा बना रहता है। साथ ही, वे यह भी कहते हैं कि वे किसी बुजुर्ग से यह नहीं कह सकते कि वह अपनी पत्नी को घसीटकर अंदर लाए। यह बयान एक ओर मानवीय संवेदना को दर्शाता है, लेकिन दूसरी ओर यह भी स्पष्ट करता है कि व्यवस्था में कहीं न कहीं गंभीर कमी है, जिसे स्वीकार करने के बजाय परिस्थितियों के हवाले कर दिया गया है।

यह घटना केवल डीग अस्पताल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के कई सरकारी अस्पतालों की स्थिति का प्रतीक बन चुकी है। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आज भी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सीमित है और जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, वे अक्सर अपर्याप्त होती हैं। ऐसे में आम लोग, खासकर बुजुर्ग और गरीब वर्ग, अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही ढूंढने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा भावुक कर देने वाली बात यह है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो खुद सहारे की उम्र में है, अपनी पत्नी का सहारा बना हुआ है। वह हर 4-5 दिन में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए उसी साइकिल का सहारा लेता है, जो शायद उसके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। यह दृश्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जहां एक ओर तकनीक और विकास की बातें हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

यह घटना समाज के लिए भी एक आईना है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने आसपास हो रही ऐसी घटनाओं के प्रति संवेदनशील हैं? क्या हम ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं या केवल वीडियो बनाकर उसे वायरल करने तक ही सीमित रह जाते हैं?

सरकार और प्रशासन के लिए यह एक चेतावनी है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार केवल बड़े-बड़े योजनाओं और घोषणाओं से नहीं होगा, बल्कि जमीनी स्तर पर सुविधाओं को मजबूत करना जरूरी है। अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में व्हीलचेयर, स्ट्रेचर और मरीजों के लिए परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी, ताकि किसी भी व्यक्ति को इस तरह की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

खाकी पर पड़ा दाग और न्याय का फैसला: राजस्थान SI भर्ती रद्द होने से उठे बड़े सवाल

राजस्थान में बहुचर्चित सब-इंस्पेक्टर भर्ती-2021 को लेकर आया हाई कोर्ट का फैसला केवल एक न्यायिक आदेश नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के लिए एक कड़ा संदेश बनकर सामने आया है। इस फैसले ने एक झटके में 859 सब इंस्पेक्टरों की नौकरी छीन ली है और हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य को फिर से अनिश्चितता के भंवर में डाल दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले में एकलपीठ के पहले दिए गए निर्णय को सही ठहराते हुए साफ कर दिया कि जब चयन प्रक्रिया की नींव ही भ्रष्टाचार और धांधली से कमजोर हो जाए, तो उसे बचाने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती।

यह पूरा मामला उस समय शुरू हुआ था जब 3 फरवरी 2021 को राजस्थान में सब-इंस्पेक्टर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी। लगभग 7 लाख 97 हजार अभ्यर्थियों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, जिनमें से करीब 3.80 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। इसके बाद 20 हजार अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट के लिए चुने गए और अंततः 3291 उम्मीदवार इंटरव्यू तक पहुंचे। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी, जिसमें हजारों युवाओं ने अपने सपनों और मेहनत को दांव पर लगाया था। लेकिन इसी प्रक्रिया के दौरान पेपर लीक और धांधली के आरोप सामने आने लगे। जांच एजेंसियों, विशेष रूप से एसओजी (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप), ने जब मामले की गहराई से पड़ताल की, तो यह सामने आया कि भर्ती प्रक्रिया में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार की जड़ें फैली हुई थीं। पेपर लीक के पुख्ता सबूत मिले और यह स्पष्ट हो गया कि चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है।

इस मामले ने उस समय और गंभीर रूप ले लिया जब राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के सदस्य रामूराम राईका और बाबूलाल कटरा की गिरफ्तारी हुई। इससे यह संकेत मिला कि केवल निचले स्तर पर ही नहीं, बल्कि उच्च स्तर पर भी अनियमितताओं की संभावना है। इस पूरे घटनाक्रम ने अभ्यर्थियों के बीच भारी आक्रोश और अविश्वास पैदा कर दिया।

28 अगस्त 2025 को एकलपीठ ने इस भर्ती को रद्द करने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। हालांकि, इस फैसले को चुनौती देते हुए चयनित अभ्यर्थी खंडपीठ में पहुंचे और मामला अंततः सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट को तीन महीने के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया था। अब खंडपीठ ने एकलपीठ के निर्णय को बरकरार रखते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि इस भर्ती को बचाने का कोई रास्ता नहीं है।

कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि जब किसी परीक्षा की शुचिता पर गंभीर सवाल उठते हैं और यह साबित हो जाता है कि उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, तो पूरी प्रक्रिया को निरस्त करना ही न्यायसंगत होता है। कोर्ट ने यह भी माना कि इस 'दूषित' चयन प्रक्रिया के कारण ईमानदार अभ्यर्थियों का हक मारा गया, जो निष्पक्ष प्रतियोगिता में सफल हो सकते थे।

हालांकि, कोर्ट ने इस फैसले के साथ एक महत्वपूर्ण राहत भी दी है। उसने निर्देश दिया है कि जब भी यह परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी, तब उन सभी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी, जो इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा थे। यह निर्णय उन युवाओं के लिए राहत भरा है, जो इस लंबे कानूनी संघर्ष के दौरान उम्र सीमा पार कर चुके हैं और अब उनके पास दोबारा मौका मिलने की उम्मीद बनी हुई है।

इस फैसले के बाद समाज और अभ्यर्थियों के बीच दो अलग-अलग धाराएं स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही हैं। एक ओर वे अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने सालों की मेहनत के बाद इस परीक्षा को पास किया था और अब अचानक उनकी नौकरी छिन गई है। उनके लिए यह फैसला एक बड़ा झटका है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष इस तैयारी में लगाए थे।

दूसरी ओर वे युवा हैं, जो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल तो हुए थे, लेकिन पेपर लीक और धांधली के कारण चयनित नहीं हो सके। उनके लिए यह फैसला न्याय की जीत के रूप में देखा जा रहा है। उनका मानना है कि यदि इस तरह की भ्रष्ट प्रक्रियाओं को रोका नहीं गया, तो योग्य और ईमानदार उम्मीदवारों को कभी भी उनका हक नहीं मिल पाएगा।

यह पूरा मामला केवल एक भर्ती परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक समस्या की ओर इशारा करता है, जो देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और भ्रष्टाचार के रूप में सामने आ रही है। यह घटना यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी परीक्षा प्रणाली इतनी कमजोर हो गई है कि उसे माफियाओं और भ्रष्ट तत्वों से बचाना मुश्किल हो गया है।

सरकार और संबंधित संस्थाओं के लिए यह एक चेतावनी है कि वे अपनी प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाएं। तकनीकी उपायों को मजबूत करना, परीक्षा केंद्रों की निगरानी बढ़ाना और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना अब समय की मांग बन चुका है।

अंततः, राजस्थान हाई कोर्ट का यह फैसला एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास है, जहां एक ओर भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया गया है, वहीं दूसरी ओर प्रभावित अभ्यर्थियों को भविष्य में एक और मौका देने की व्यवस्था भी की गई है। यह निर्णय भले ही तत्काल रूप से कई लोगों के लिए कठिन हो, लेकिन दीर्घकाल में यह व्यवस्था की शुद्धता और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम के रूप में देखा जाएगा।